fo"k; lwph

भाजपा पदाधिकारियों की बैठक 5

लेख

''कमल'' की प्रकृति है खिलना
—प्रभात झा........................ 7
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए बिना..
—शांता कुमार..................... 24

अन्य

डॉ. मनमोहन सिंह से 14 प्रश्न.11
बेंगलूर में भाजपा का महापौर. 13
दंतेवाड़ा में नक्सली हमला...... 15
यूपीए की अफगान नीति......... 19
हिन्दूइज्म का इन्साइक्लोपीडिया.20
रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट..... 22

राज्यों से

दिल्ली.................................... 26
असम...................................... 27
उत्तराखण्ड.............................. 28
मध्य प्रदेश.............................. 29

सम्पादक
çHkkr >k] lkaln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kekZ
latho dqekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/kesZUæ dkS'ky
fodkl lSuh
सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ihih&66] lqczã.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887
lnL;rk gsrq % +91¼11½&23005700
सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

दया के समान कोई पुण्य नहीं और हिंसा के समान कोई पाप नहीं।

-श्रीमद्भागवत गीता

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

lEikndh;

जिन्हें जिंदगी देना चाहिए वो मौत परोस रहे हैं

21 अप्रैल, 2010 भाजपा के लिए इतिहास बनाने का दिन। महंगाई से त्रस्त जनाक्रोश का सैलाब दिखाने का दिन। गरीबों के लिए महंगाई मौत बनती जा रही है। गरीबों को नई जिंदगी देने के संघर्ष का बिगुल लाखों भाजपा कार्यकर्ता संसद भवन पर बजाएंगे। नए तेवर से और नए कलेवर से नेतृत्व को दिशा देने में जुटे नितिन गडकरी का ऐलान ''अब सड़कों पर संघर्ष होगा'' की शानदार तैयारी की शुरूआत, विचारों में अडिगता और सड़कों के संघर्ष को अंजाम देने की शुरूआत ही किसी संगठन के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। 21 अप्रैल भारतीय राजनीति में विश्वास के जागरण का दिन होगा। कथनी और करनी का अंतर मिटेगा। राजनीति में घट रही विश्वसनीयता और उपज रही अविश्वसनीयता को विराम देने का दिन होगा। इसलिए हस्ताक्षर अभियान की गूंज भारत की गली–गली में गूंज रही है। लोग स्वीकार कर रहे हैं कि यूपीए–II को हम अस्वीकार करते हैं। 2009 के मई में जिस यूपीए सरकार को जनता ने चुना था अब जनता अहसास कर रही है कि वह भारी भूल थी।

संघर्ष का सतत् जारी रहना, संगठन को सहज लोकप्रिय बनाने में सहायक होता है। जनता आज सर्वत्र यह कहती है कि हमारी लड़ाई कोई ईमानदारी से नहीं लड़ रहा है। इसलिए भाजपा का यह 'संसद चलो' आह्वान गरीबों को स्वर देने का पैगाम है। बहुत सरकारें आयीं और गईं। लेकिन किसी सरकार ने गरीबों के पेट पर लात मारने की कोशिश नहीं की, निवाला छिनने का प्रयत्न नहीं किया, खून निकालने का काम नहीं किया, शोषित का शोषण नहीं किया। दुर्भाग्य यह है कि आम आदमी की सरकार सरेआम बीच चौराहे पर आम आदमी की जान लेने पर आमादा है। महंगाई ने आम आदमी को देश से काट दिया। रोटी की जुगाड़ में लोग राष्ट्र को भूल रहे हैं। ऐसे दिन भारत ने आजादी के बाद कभी नहीं देखे।

संविधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि नागरिकों के जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है पर वाह री यूपीए–II, वाह री सोनिया, वाह राहुलजी, आप एक संवैधानिक प्रधानमंत्री को पपेट बनाने में तो माहिर हैं पर देश की महंगाई कम करने का तरीका आपको नहीं मालूम। भारत को कांग्रेस के युवराज अपनी जिंदगी का पिकनिक–स्थल मानते हैं। हनीमूनी स्वभाव से वे भारत के कुछ राज्यों में जाते हैं, चापाकल पर नहाते हैं। उनके नहाते शरीर की वीडियो फिल्म बनती है। मीडिया उसे दिखाती भी है पर क्या उनकी इस राजनीतिक हरकतों से गरीबों को निवाला मिल सकता है।

इंतहा तो तब हो गई जब संसद में वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण के 189 बिन्दुओं में दो शब्द भी ''युवा और बेरोजगार'' को कोई प्राथमिकता नहीं दी। ये दो शब्द बजट–पत्र में कहीं नहीं है। क्या यह
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

भारत के युवा और बेरोजगारों का अपमान नहीं है? अपनी राजनीतिक नौटंकियों से भारत की समस्याओं का हल नहीं होगा।

शायद देश को जानकारी नहीं होगी और होगी भी तो यह कोई गर्व की बात नहीं है। पिछले दिनों वह बात स्वयं सत्य होती जा रही है कि भविष्य में विश्वयुद्ध पानी को लेकर होगा। भोपाल और इंदौर में एक बाल्टी पानी के लिए चार लोगों को मौत के घाट उतारना, क्या यह संकेत नहीं है। हम 62 साल बाद पानी की समस्या का निदान नहीं कर पाए। एक बाल्टी पानी के लिए मौत। दो जून रोटी के लिए मौत। बेरोजगारी दूर करने के लिए मौत। निरपराधों को नक्सलियों द्वारा मौत। आखिर हम किस देश में जी रहे हैं? हमारा लोकतंत्र कैसा है? लोक शासन कैसा है जिन्हें जिंदगी देने का काम दिया गया है वे सरेआम मौत परोस रहे हैं।

आज स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी न किसी राजनीतिक दल को संघर्ष के लिए सड़कों पर आना ही होगा। संघर्ष की शुरूआत–राजनीतिक दल द्वारा जरूर होगी पर जनता को भी इसमें भागीदारी दर्शाना होगा। आज भारत को एक जबरदस्त जनांदोलन की जरूरत है। भारत की भारतीयता संकट में है सीमाएं संकट में हैं। आजादी के समय के विवाद सुलझे नहीं और उलझे ही हैं। 21 अप्रैल 2010, 'चलो दिल्ली–चलो संसद' यह मात्र नारा नहीं, यह भारत के ज्वलंत समस्या के निदान की अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति को समाज का सामूहिक स्वर चाहिए। महंगाई कोई दलीय समस्या नहीं, राष्ट्रीय समस्या है। जब हम कहते हैं राष्ट्रीय समस्या तो इस संघर्ष के यज्ञ में हर उस नागरिक की आहुति की आवश्यकता है जो महंगाई से परेशान हैं। 21 अप्रैल, 2010 को लगना चाहिए कि आम आदमी को धोखा देने का परिणाम क्या होता है? वहीं जनता जब सड़कों पर आती है तो देखिए, सत्ता की कुर्सी कैसे हिलती है। ■

गलत नीतियों से महंगाई बढ़ी : गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा लोगों को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो देश के गोदामों में अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार विदेशों से महंगा अनाज खरीद रही है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को महंगाई बढ़ने के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।

पार्टी के स्थापना दिवस पर वीपी हाउस दिल्ली में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात अर्थशास्त्री डा. सिंह से देश को बेहतर आर्थिक नीतियों की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि चीन के 2.7 प्रतिशत, अमेरिका के 2.6 प्रतिशत, यूरोप के 0.9 प्रतिशत, मलेशिया के 1.3 प्रतिशत और सिंगापुर के 0.2 प्रतिशत की तुलना में भारत में मुद्रास्फीति 11 प्रतिशत है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के किसानों से 9.50 रूपये प्रति किलो की दर से गेहूं खरीदे गए दूसरी ओर अब खराब गुणवत्ता वाले गेहूं 19 रूपये प्रति किलो की दर से विदेशों से खरीदे जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितीन गडकरी ने कार्यक्रम के शुभारम्भ में भाजपा के स्थापना दिवस पर देश भर के कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा विचारधारा आधारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी हैं।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार नक्सलियों के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी भाजपा साथ है। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने देश में बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या पर भी विरोध जताया और कहा कि वोट की राजनीति छोड़कर कांग्रेस देश की सोचे। भाजपा की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ओपी कोहली, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल एवं श्री थावरचंद गहलोत आदि ने भी सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव सुश्री आरती मेहरा, कु. वाणी त्रिपाठी, श्री भूपेन्द्र यादव, डा. हर्षवर्धन, मांगेराम गर्ग, डा. नंदकिशोर गर्ग, मेयर कंवर सेन, निगम के नेता सुभाष आर्य, समेत दिल्ली के तमाम छोटे–बड़े नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विधायक श्री रमेश बिधूड़ी ने किया। ■

कार्यकर्ता की तरह काम करें नेता : गडकरी

Hkkजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में दो टूक कहा कि पार्टी के हर जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी को महीने में कम से कम आठ दिन अपने क्षेत्र में प्रवास करना ही होगा ताकि वह जमीन से जुड़े और नए लोगों को पार्टी से जोड़ें। साथ उन्हें अपनी पहचान नेता नहीं, कार्यकर्ता की बनानी होगी। पार्टी में हर राज्य की संगठनात्मक, राजनीतिक व चुनावी रूपरेखा भी अलग–अलग तय की जाएगी। पार्टी के नए राष्ट्रीय

पदाधिकारियों की पहली बैठक से ही श्री गडकरी ने पार्टी का व्यापक जनाधार बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए साफ कर दिया है कि वह हवा में नहीं, जमीन पर काम करने में विश्वास करते हैं। वह अपनी पहचान नेता नहीं, कार्यकर्ता के रूप में रखना चाहते हैं। इसलिए बाकी लोग

अनुमोदित किया गया प्रस्ताव

Hkkरतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में माओवादियों द्वारा सुरक्षाबलों पर किए गए बर्बर, अमानवीय और राष्ट्र विरोधी हमले की घोर निंदा करती है, जिसमें भारी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्य पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई थी। यह हमला राष्ट्र को इस कठोर सच्चाई की याद दिलाने वाला है कि संप्रग शासन के विगत 6 वर्षों में माओवादियों के भौगोलिक विस्तार में और उनकी फायर करने की शक्ति की तीव्रता में कई गुना वद्धि हुई है। यह हमला, जिससे हमारे सुरक्षाबलों के जीवन को भारी हानि पहुंची है, भारत की देशभक्त और राष्ट्रवादी शक्तियों के लिए एक चुनौती बन गया है। इसका सामना करने के लिए हमको विध्वंसक माओवादी ताकत के विरूद्ध जी–जान की लड़ाई शुरू करनी होगी।

माओवादी आंदोलन का उद्देश्य हिंसा के द्वारा भारत के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करना है। माओवादी गरीबी और पिछड़ेपन से जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं तथा मजबूती पाते है। वे अपनी विध्वंसक गतिविधियों से पिछड़े क्षेत्रों के विकास को अवरूद्ध कर रहे हैं। देश के लगभग 200 जिलों में माओवादियों की अच्छी–खासी उपस्थिति है। माओवादी लोगों से धन ऐंठते रहते हैं। माओवादी विदेशी जमीन से प्राप्त हुए और पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए गोला–बारूद पर निर्भर रहते हैं। उक्त 200 जिलों में सिविल प्रशासन का प्रभाव नगण्य है।

यद्यपि 2004–09 की अवधि के दौरान माओवादियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई, तो भी केन्द्रीय सरकार मूक–दर्शक बनी रही। झारखंड, छत्तीसगढ़ और आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का चुनावों के समय माओवादियों से मेलजोल रहता था।

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा की गई पहल का केन्द्र ने विरोध किया था। 2009 के बाद भी जब गृहमंत्रालय ने अपने रवैये में परिवर्तन करने का प्रयास किया तब भी सरकार में मतैक्य का अभाव था। संप्रग के कुछ वर्गों ने कुछ राज्यों में माओवादियों के पक्ष में प्रचार भी किया था। पश्चिम बंगाल इसका जीता–जागता उदाहरण है। वर्तमान में, माओवादी गतिविधियों के बारे में सरकारी प्रतिष्ठान का सतर्कता–तंत्र नाम मात्र का है। इस सतर्कता–तंत्र को मजबूत किए जाने की महती आवश्यकता है। अर्ध–सैनिक बलों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सुदृढ़ करना, उनका आधुनिकीकरण करना तथा उन्हें यथेष्ठ फायर पावर से सुसज्जित करना तत्काल लाज़मी है।

भारतीय जनता पार्टी माओवादियों के विरूद्ध सदैव ठोस और सक्रिय रवैया अपनाने की पक्षधर रही है। आज, जब स्थिति अत्यधिक गंभीर है, भाजपा सभी राजनीतिक दलों और सभी तरह का मत रखने वाले लोगों का आह्वान करती है कि वे माओवाद को समाप्त करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ें। भाजपा भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों का भी आह्वान करती है कि वे माओवादियों के विरूद्ध एकी.त रणनीति तैयार और सुदृढ़ करें। एक राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति के रूप में भाजपा इस राष्ट्रीय संकल्प की अगुवाई करेगी।■

भी ऐसा ही करें। तभी पार्टी लक्ष्य हासिल कर सकेगी।

बैठक के बाद राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार ने बताया कि केंद्र से लेकर जिला व मंडल स्तर तक प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाएंगे जहां विचाराधारा पर जोर के साथ अत्याधुनिक संचार सुविधाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। श्री गडकरी ने संसदीय मामलों के लिए लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली को देश हित के अनुरूप उचित रणनीति बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि नाभिकीय क्षतिपूर्ति विधेयक व विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक के मामले में केंद्र सरकार लुकाछिपी का खेल खेल रही है। दोनों विधेयकों के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक पर श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह इसका पूरा समर्थन देकर राज्य सभा से पारित कराया, उसी तरह लोकसभा में भी समर्थन करेगी, लेकिन वह मार्शलों के उपयोग का विरोध करेगी।

इस मामले पर आम सहमति जुटाने का दायित्व सरकार का है। वित्त विधेयक पर विपक्षी खेमे के अन्य दलों के साथ भाजपा भी कटौती प्रस्ताव लेकर आ रही है। बैठक में पार्टी की 21 अप्रैल की महंगाई विरोधी रैली की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। श्री गडकरी ने सभी पदाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदारियां सौंपते हुए कहा कि जो पदाधिकारी जिस राज्य से है, वह वहां पर इसकी सफलता के लिए काम करे। रैली के लिए 30 ट्रेन व बड़ी संख्या में बसों को बुक किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार ने बताया कि गत दिनों छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ जवानों पर किए गए घातक हमले का भाजपा कड़ा विरोध करती है। इस हमले में शहीद हुए जवानों को बैठक के शुभारम्भ में ही श्रद्धांजलि दी गई। श्री अनंत कुमार ने कहा कि भाजपा ने देश की गम्भीर आंतरिक संकट नक्सली समस्या के संदर्भ में इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। ■

कोलकाता : पश्चिम बंगाल

कांग्रेस ने बच्चन को बनाया खलनायक

कांग्रेस बनाम बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन विवाद पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। अमिताभ को खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। भाजपा शुरु से ही अमिताभ के समर्थन में है। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद पहली बार कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि अमिताभ बच्चन दाऊद इब्राहिम नहीं है। कांग्रेस उन्हें क्यों खलनायक के तौर पर पेश कर रही है। यह सब सोनिया गांधी के कारण हुआ है। क्योंकि सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करती हैं और कांग्रेस में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वे सोनिया के खिलाफ कुछ बोल सकें। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की निजी संपत्ति बन गई है।

श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा मुस्लिम या किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया था। हम अल कायदा और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। कांग्रेस ऐसा ही कर रही है। ■

पटना में होगी आगामी भाजपा की कार्यकारिणी बैठक

भाजपा की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में पटना में होगी कार्यकारिणी संभवतः मई के अंत में होगी। 8 अप्रैल को दिल्ली में नीतिन गडकरी की अध्यक्षता में केंद्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक हुई। अन्य मुद्दों के साथ साथ पहली कार्यकारिणी पटना में आयोजित करने का भी फैसला हुआ। ■

''कमल'' की प्रकृति है खिलना उसे कोई रोक नहीं सकता

&çHkkr >k

Hkkरतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल, 2010 को तीस वर्ष की हो गयी। वैसे जनसंघ के जन्म से जोड़ें तो लगभग 59 वर्ष हो जाते हैं। आजादी के बाद गठित राजनैतिक दलों में राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनैतिक दल देश में उभरा तो वह पूर्व में भारतीय जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी। सत्ता और विपक्ष में जितने भी राजनैतिक दल देश में बने वह कभी न कभी टूटी, बंटी और समाप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी को यह गौरव जाता है कि उसने जनसंघ के समय में यदि अपना अस्तित्व समाप्त किया तो वह भी राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना के लिये। जनसंघ के तत्कालीन नेताओं ने आपातकाल की काली साया के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया और चुनाव के समय ''जनता पार्टी'' का गठन हुआ तो जनसंघ ही एकमात्र राजनैतिक पार्टी थी, जिसने अपने चुनाव चिह्न ''दीपक'' को राष्ट्रहित के लिये जनता पार्टी में विलीन करते हुये बुझा दिया। राजनैतिक ईमानदारी का ऐसा साहसिक कदम कम ही देखने को मिलता है। वहीं एक बात और है कि अपने अस्तित्व को जब जनता पार्टी ने ओछी हरकतों से चुनौती देना शुरु किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जनता पार्टी के कुछ तत्कालीन नेताओं ने बवाल खड़ा किया तो ''जनसंघ घटक'' के लोगों ने कहा कि आप जनता पार्टी से हमें निकाल दें पर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना नाता नहीं तोड़ेंगे। आपसे तो हमारा नाता आज का है, संघ से तो हमारा नाता बचपन से है। जनसंघ घटक के नेताओं को जब दोहरी सदस्यता के सवाल पर जपा से बाहर किया तो 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के सभी लोगों ने एक राजनैतिक पार्टी बनाई और उसका नाम ''भारतीय जनता पार्टी'' रखा और चुनाव चिन्ह ''कमल का फूल'' रखा।

भारतीय जनता पार्टी को यह गौरव जाता है कि उसने जनसंघ के समय में यदि अपना अस्तित्व समाप्त किया तो वह भी राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना के लिये। जनसंघ के तत्कालीन नेताओं ने आपातकाल की काली साया के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया और चुनाव के समय ''जनता पार्टी'' का गठन हुआ तो जनसंघ ही एकमात्र राजनैतिक पार्टी थी, जिसने अपने चुनाव चिह्न ''दीपक'' को राष्ट्रहित के लिये जनता पार्टी में विलीन करते हुये बुझा दिया। राजनैतिक ईमानदारी का ऐसा साहसिक कदम कम ही देखने को मिलता है।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनैतिक जीवन के तीन दशक में अनेक उतार–चढ़ाव देखे। एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि देश में सन् 1984 में भारतीय जनता पार्टी को देशभर में सिर्फ दो लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। एक बार तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अमान्य कर दिया। पर बात ऐसी नहीं थी। इंदिरा जी की श्रद्धांजलि लहर ने चुनावी गणित बिगाड़ दिये। यहां एक बात गौर करने वाली है कि आखिर दो सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव के बाद लगातार लोकसभा की सीटों में वृद्धि करती गई और एक समय ऐसा आया कि देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। स्थिति यहां तक आ गई भारतीय जनता पार्टी–नीत एनडीए का गठन हुआ और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 24 राजनैतिक दलों को साथ लेकर वे निरंतर सरकार चलाते रहे। यही नहीं अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी बनीं।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को अपनी तीसवीं वर्षगांठ पर जो बात सोचने और समझने की है कि आखिर वे क्या कारण थे कि दो सीटों पर सिमट चुकी भारतीय जनता पार्टी मात्र दस–बारह वर्षों में देश की सबसे बड़ी अधिकतम सांसदों वाली और भाजपा–नीत एनडीए की सरकार बनी और शानदार चली। अगर भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ता ईमानदारी से सन् 1985 से लेकर 1991

–1997 –1998 और सन् 2000 के बीच के कार्यकाल का विश्लेषण करें तो शायद उन्हें वर्तमान परिस्थिति में न केवल काम करने में सुविधा होगी, बल्कि वो दिन दूर नहीं जब पुनः देश की जनता भाजपा को सरकार चलाने का अवसर प्रदान करेगी।

अटलजी किसी भी विषय पर निर्णय पूर्व बहुत बहस करते थे और जब सब मिलकर कोई ऐसा भी निर्णय लेते थे जो अटलजी के मनोनुकूल नहीं होता था तो भी अटलजी कहते थे, 'जो पंचों का फैसला।' अटलजी सामूहिक निर्णय तथा बहुमत की सहमति की अवहेलना कभी नहीं करते थे।

भारतीय जनता पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में लगातार रहते हुये सत्ता में आयी। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिये और एक न एक दिन वे बनेंगे, ऐसा विश्वास जन–जन के मन में प्रबल रहा, जब अटलजी विपक्ष में थे। अटलजी प्रधानमंत्री बनें, भाजपा सत्ता में आए, यह जन–जन का सपना बन चुका था। वर्षों तक अपनी ''वाणी'' से जन–जन को बांधने का जो अथकनीय प्रयास अटलजी ने किया अब शायद ही कोई राजनेता कर पायेगा। उन्होंने अपनी वाणी को जन–जन की वाणी बना दी और वे देश के एक–एक नागरिक के अभिव्यक्ति के केन्द्र बने। वे जब पद पर नहीं थे तब भी उनके कद को किसी ने चुनौती नहीं दी।

यहां इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अटलजी को जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा में उनके दल के कार्यकर्ताओं ने एकमेव नेता माना। वे योग्य तो थे ही, वे उपयोगी भी थे, साथ ही उनकी ग्राह्यता भी जबर्दस्त थी। आज परिस्थिति बदली हुई है। यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि भाजपा नेतृत्व को यह समझना आवश्यक होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की किन–किन कारणों से ग्राह्यता थी। लोग या दल के सभी नेता उनकी बात क्यों नहीं काटते थे। कहा जाता है कि अटलजी किसी भी विषय पर निर्णय पूर्व बहुत बहस करते थे और जब सब मिलकर कोई ऐसा भी निर्णय लेते थे जो अटलजी के मनोनुकूल नहीं होता था तो भी अटलजी कहते थे, 'जो पंचों का फैसला।' अटलजी सामूहिक निर्णय तथा बहुमत की सहमति की अवहेलना कभी नहीं करते थे।

अटलजी के साथ वर्षों काम करते रहे अनेक नेता कहते हैं कि अटलजी को देखकर सहज आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसा नहीं कि अटलजी कभी चुनाव नहीं हारे। एक समय तो ऐसा आ गया कि उनका जहां जन्म हुआ, उस ग्वालियर से ही चुनाव हार गए। अटलजी चुनाव हारे पर जन–जन के ''मन'' को नहीं हारे और उनकी हार का दुख सिर्फ उनको या भाजपा को ही नहीं सारे देश को हुआ।

सन् 1985 से लेकर सन् 2000 के बीच अटलजी और आडवाणीजी की जो भारतीय राजनीति में भूमिका रही वह सदैव स्मरणीय ही नहीं बल्कि राजनैतिक विश्लेषकों के लिए वह आगे चल कर शोध का विषय होगा। भारतीय राजनीति में अटलजी और आडवाणीजी के बीच जो वैचारिक सेतुबंध और मानसिक अनुबंध के साथ–साथ जो हार्दिक अनुबंध था व न केवल अनुकरणीय बल्कि भारतीय राजनीति में भविष्य में लोग इसे मिसाल के रुप में प्रस्तुत करेंगे। इन दोनों नेताओं के बीच ''विश्वास'' का अनुपम संगम रहा। यही कारण था कि ऊपर से लेकर नीचे तक कार्यकर्ता अपने–अपने स्थान पर विश्वास की कड़ी से जुड़े रहे। राजनैतिक दलों में ही नहीं राष्ट्र और समाज के कार्यों में आज विश्वास का गहरा संकट उत्पन्न हुआ है। इसे हर हाल में मिटाना होगा। संघर्ष और साधना के पथ को पकड़ना होगा। आडवाणीजी की रथ यात्राओं ने भाजपा को देश में एक नई पहचान दी। जिन–जिन मुद्दों को लेकर वे भारत की सड़कों पर निकले, देश ने न केवल स्वीकारा, बल्कि अंतर्मन से सराहा।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी की एकात्मता यात्रा ने इतिहास रचा। भारत के मनमानस को झकझोर दिया। इन यात्राओं से जो एक और बात निकली कि भाजपा के दूसरी पांती के लोगों को जनता ने देखा। दूसरी पांती का नेतृत्व उभरा। सच में यह राजनैतिक दलों की दृष्टि से देखें तो अनुकरणीय प्रयास था। जगह–जगह नेतृत्व को उभारने के साथ–साथ संघर्ष और साधना से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का क्रम सदैव

आज की पीढ़ी को, जो भाजपा में काम करते हैं उन्हें इस बात का अध्ययन तो करना ही चाहिए कि आखिर जनसंघ का जन्म क्यों हुआ और वे किस राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन के लिये राजनीति में काम कर रहे हैं। आजकल राजनीति में विद्यार्थी ऐसे आ रहे हैं, जो पढ़ते नहीं हैं परीक्षा भी नहीं देते, पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं।

चलते रहना चाहिये।

''राजनैतिक दल'' के बारे में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे कहा करते थे कि यह मनुष्यों के बीच कार्य करने वाला संगठन होता है। नेतृत्व में मातृत्व भाव होना चाहिए। कार्यकर्ता को मनुष्य की नजरों से देखना चाहिये न कि मशीन की नजर से। मनुष्यों का संगठन चलता है सहानुभूति से, संवेदना से, नैतिकता से, परिश्रम से, निष्ठा से, आस्था से, समर्पण से, नैतिकता और प्रमाणिकता से, साथ ही साथ संगठन चलता है मनुष्यता और परोपकार की भावना से।

ठाकरे जी अक्सर यह बात अपने भाषणों में कहा करते थे। वे कहते थे कि जमीनी हकीकत समझो, नहीं तो धोखा खाओगे।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपने जीवन को संगठन–कार्य में आहूत कर देने वाले स्व. सुंदर सिंह भण्डारी कहते थे कि दूसरे के मन को जीतना है तो पहले अपने तन और मन को छोड़ो। वे अनुशासन के जबर्दस्त हामी थे। वे कहते थे कि जो उतर जाता फिर वह दोबारा चढ़े भी तो लोगों के मन में कभी नहीं चढ़ पाता।

भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की अब तक की यात्रा में भला उन दो विभूतियों को हम कैसे भूल सकते हैं। एक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डॉ. मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे तो पंडित दीनदयाल जी भारतीय राजनीति को ''एकात्म मानव दर्शन'' देने वाले प्रणेता थे।

आज की पीढ़ी को, जो भाजपा में काम करते हैं उन्हें इस बात का अध्ययन तो करना ही चाहिए कि आखिर जनसंघ का जन्म क्यों हुआ और वे किस राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन के लिये राजनीति में काम कर रहे हैं। आजकल राजनीति में विद्यार्थी ऐसे आ रहे हैं, जो पढ़ते नहीं हैं परीक्षा भी नहीं देते, पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं।

भाजपा भाग्यशाली है कि उसके सिर पर ऋषि तुल्य एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदैव स्नेह और मार्गदर्शन बना रहता है। भाजपा भाग्यशाली इन मायनों में भी है कि उसके साथ संघ परिवार का भी समय–समय पर योगदान रहता है। भाजपा भारत की नैसर्गिक पार्टी है। उसे जनता कभी नकार नहीं सकती, बशर्ते भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ता यह तय कर ले कि उसे भारत के उस अंतिम छोर पर बैठे दरिद्रनारायण की सेवा करना है जिसका कोई नहीं है, वहीं अंत्योदय और सर्वोदय की भावना को कभी बुझने नहीं दें। भाजपा का चुनाव चिन्ह है ''कमल''। कमल की प्रकृति है ''खिलना''।

अतः 6 अप्रैल 1980 को अटलजी ने भाजपा के प्रथम अधिवेशन में मुंबई में कहा था, 'अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा।' भाजपा तय कर ले तो कमल को खिलाने में देश का जन–जन जुट जाएगा।■

(लेखक भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव व सांसद हैं)

बाराबंकी : उत्तर प्रदेश

नफरत फैलाने वाली किताबों पर पाबंदी लगाए केन्द्र सरकार : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नदवा कालेज में चल रही नफरत की बीज बाने वाली कोर्स की किताबों की जांच कर केन्द्र सरकार को उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। भाजपा का मानना है कि नफरत के बीज पैदा करने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। श्री सिंह विधान परिषद सदस्य रामनरेश रावत के नगरपालिका हाल में हुए कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। श्री सिंह के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने पिछले दिनों लखनऊ के अधिवेशन में फरमान जारी किया कि भारत इजराइल से दोस्ती खत्म करे। यह गलत है। किसी भी देश से एकदम से संबंध खत्म नहीं करने चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह ने अमिताभ बच्चन पर चल रही कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती पर कहा कि गैरजरूरी विवाद खड़ा किया गया। अमिताभ बच्चन सम्मानित नागरिक हैं। उनका कला और मनोरंजन के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणकारी सरकार की भूमिका नहीं निभा रही हैं। कानून व्यवस्था बहुत खराब है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

श्री राजनाथ सिंह ने केन्द्र सरकार के गेहूं का समर्थित मूल्य किसानों के लिए ग्यारह सौ रूपए प्रति कुंतल करने पर कहा कि विदेशों से गेहूं सोलह सौ रूपए प्रति कुंतल खरीदा जा रहा है। किसानों के मान–सम्मान के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य सोलह सौ रूपए प्रति कुंतल घोषित करना चाहिए। केन्द्र और सूबे की सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापतिराम त्रिपाठी, पंकज सिंह, विधायक रामनरेश रावत, सुधीर कुमार सिंह सिद्धू, संतोष सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।■

चीनी घुसपैठ : देश की बाह्य सुरक्षा को खतरा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितीन गडकरी द्वारा श्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड व सांसद के नेतृत्व में गठित एक पांच सदस्यों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जिसके सदस्य श्री राजीव प्रताप रुडी, सांसद, राज्यसभा, श्री राजन सुशान्त, सांसद, श्री तापिर गांव, पूर्व सांसद और श्री निर्मल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर शामिल है, ने चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र मे घुसपैठ संबंधी समाचारों के अध्ययन हेतु अपने द्वितीय चरण की यात्रा लेह–लद्दाख में समाप्त की। इसके पूर्व यह प्रतिनिधिमंडल अरूणाचल प्रदेश का दौरा भी कर चुका है और अगले राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के पूर्व उत्तराखंड व सिक्किम के अध्ययन के बाद चीन द्वारा निरंतर घुसपैठ की रिपोर्ट भी सौंपेगा। इस प्रतिनिधिमंडल ने लेह–लद्दाख के आठ सौ किलोमीटर से अधिक के इलाकों का दौरा किया और सीमित ऑक्सीजन व भयंकर ठंढ़ के वातावरण में जाकर इसका अध्ययन किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

भाजपा प्रतिनिधि मण्डल ने द्वितीय चरण की यात्रा के पश्चात सौंपी रिपोर्ट

1 सन् 1962 ईस्वी में चीन ने भारत के अधिसंख्य भू–भाग पर कब्जा किया था वो पूर्णरूपेण स्व॰ जवाहर लाल नेहरू की कूटनीतिक विफलता थी जिसका भौगोलिक नुकसान व प्रभाव हम आज भी महसूस कर रहे है। आज भी संप्रग सरकार की नीतियां और नेहरू की चीन नीतियों में कोई भिन्नता नहीं है जिसके कारण आज देश पर खतरा मंडरा रहा है।

2 सन् 1962 ईस्वी से 1996 ईस्वी तक औसतन सभी सरकारों ने चीन द्वारा बड़े पैमाने पर भारतीय भू–भाग पर कब्जा या घुसपैठ किये जाने की घटनाओं को नजरअंदाज किया है।

3 एक तरफ जहाँ चीन ने अपने सीमा की तरफ हजारों किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण कर लिया है वहीं दूसरी तरफ भारतीय सीमा में न के बराबर संरचनात्मक कार्यों ने लेह–लद्दाख के निवासियों को हीं नहीं बल्कि भारतीय सेना व आई टी बी पी के जवानो को भी हताश व निराश किया है। विवादित अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा तथा निरंतर बहती सिंध की धारा एवं उससे सटे चारागाहों के भौगोलिक परिवर्तन के कारण घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ गई है और जो लोग इनकी सुरक्षा कर रहे है उन्हें इसके बारे में सरकार की मंशा क्या है, दूर–दूर तक पता नहीं है

4 चीन ने अटकरावपूर्ण (Non-Conflict) कूटनीति का और चरवाहों, भेड़िहारों व बंजारों का इस्तेमाल कर धीरे–धीरे भारतीय भू–भाग में प्रवेश करने की नई कूटनीति बनाई है जिसका प्रभाव आज इस सीमा पर दिख रहा है।

5 चीन ने नरेगा व अन्य विकास की योजनाओं एवं अन्य निर्माण कार्यों पर अपने प्रभाव का उपयोग कर रोक लगाया है जिसका उदाहरण हाल ही में डेमचक में दिखा जहां नरेगा योजनान्तर्गत हो रहे पथ निर्माण पर रोक लगाया गया।

6 लद्दाख के मूल अधिकारों के हनन के कारण भारतीयता से परिपूर्ण वहां के निवासी जो चीन द्वारा कब्जा किये गये अपने जमीन की वापसी हेतु संकल्पित है, आज चीन के निशाने पर है।

7 भारत सरकार द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा परमिट जारी रखने के कारण आजकल भारतीय पर्यटकों को भी वहां जाने की अनुमति नहीं मिलती है जिसके कारण चीन द्वारा घुसपैठ व अतिक्रमण से भारत अनभिज्ञ रहता है।

8 चूंकि लेह का क्षेत्र विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के लिए संघर्षपूर्ण नहीं है इसलिए भारतीय सेना आई टी बी पी की उपस्थिति न्यूनतम है जिसका लाभ चीनी सेना घुसपैठ के लिए उठाती है।

आज मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के क्षेत्र से की जाती है जिसमें श्रद्धालुओं को पन्द्रह से बीस दिन का समय लगता है जबकि यही यात्रा लद्दाख क्षेत्र की तरफ से की जाय तो लगभग 48 घण्टे का समय लगेगा।

इस मार्ग को बाधित रखना चीन की एक सोची–समझी चाल है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि केन्द्र सरकार अपनी सीमा की सुरक्षा करना तो दूर इन विषयों पर चर्चा करने से परहेज करती है। ■

गडकरी ने पूछे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से १४ प्रश्न

पिछले 20 सप्ताहों में खाद्य मुद्रास्फीति 17 से 20 प्रतिशत रही

1. आखिर गलती कहां हुई है?

   भारत में 11 प्रतिशत की मुद्रास्फीति विश्व में सबसे अधिक है। यदि देखें तो चीन की जीडीपी वृद्धि 9.5 प्रतिशत (भारत की 7.2 प्रतिशत) रही, फिर भी चीन की मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत और भारत की 11 प्रतिशत रही।
2. क्या आप इस बात से इंकार करते हैं कि विश्व की 1 से 2 प्रतिशत मुद्रास्फीति के मुकाबले भारत की मुद्रास्फीति 11 प्रतिशत है?

   अन्य देशों की तुलना में भारत में चीनी की कीमतों में दुगुनी और गेहूं की कीमतों में 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
3. क्या यह सच नहीं है कि विश्व बाजार की तुलना में खाद्य पदार्थों की कीमतें 80 प्रतिशत से अधिक है?

Hkko :-@fd-xk-		
en	2004	24
गेहूं	9	24
चावल	10	28
चीनी	14	37
मूंगफली तेज	40	100
चना दाल	25	52
तुर/मूंगदाल	24	88
दूध	14	32
मिट्टी का तेल/प्रति लि.		

4. क्या यह असलियत नहीं है कि आपके शासन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में दोगुनी वृद्धि हुई।
5. क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि दलितों और मध्य वर्गीय लोगों के लिए गुजारा करना तक मुश्किल हो गया है?

   48 लाख टन चीनी का निर्यात 12.50 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर किया गया और इसका पुनः आयात 22 से 32 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर हुआ।

6. आपने चीनी का निर्यात 12.50 रूपए प्रति कि.ग्रा. करना और 22 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर आयात करना बेहतर समझा परन्तु बफर स्टॉक बनाना ठीक नहीं समझा। क्या आप लोगों के सामने इस बारे में जवाबदेह नहीं है?
7. क्या आप अपनी इस घोटालेबाज निर्यात–आयात नीतियों से नावाकिफ रहे हैं?

   ''योजना आयोग ने अपनी 2005 की रिपोर्ट में बीपीएल (गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों की) जनसंख्या को 31 करोड़ बताया था। तेन्दुलकर समिति की दिसम्बर 2009 में से 42 करोड़ बताया था और फिर भी आपका दावा रहा है कि गरीबी घटी है''।
8. फिर ऐसा क्यों है कि ग्रामीण भारत के 42 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है? क्या आप सचमुच उन्हें खाद्यान्न दे रहे हैं?
9. सरकारी गोदाम खाद्यान्नों से आवश्यकता से अधिक भरे पड़े हैं और सड़ रहे हैं। फिर भी कीमतें क्यों आसमान छू रही हैं और क्यों गरीब लोग पेटभर खाना भी नहीं

खा पाते हैं?

10. क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्सेना कमेटी ने बताया था कि 51 प्रतिशत गरीब लोगों को बीपीएल राशन कार्ड नहीं दिए गए और उन्हें खाद्यान्नों से वंचित रखा गया?

दिसम्बर 2009 में कृषि नकारात्मक– 0.2 प्रतिशत रही। इसके बाद भी सरकार ने कृषि विकास के लिए अपने कुल 12 लाख करोड़ बजट में से मात्र मामूली सा 900 करोड़ रूपए अर्थात् 0.075 प्रतिशत का प्रावधान किया।

11. आपको इस सम्बन्ध में क्या कहना है?

en	fd lkuk dk fn;k x;k eY; :-@ifr fd-xk-	[knjk eY; :-@ifr fd-xk-	@ vrj
चावल	9.80	23.00	135
तुर दाल	23.00	90.00	290
मूंग	27.60	70.00	150
गेहूं	10.80	17.00	65
ज्वार	8.60	13.00	50
बाजरा	8.40	15.00	75

12. ऐसा क्यों है कि किसान को सबसे कम मिलता है, तो उधर आम आदमी को सबसे ज्यादह चुकता करना पड़ता है?

नेशनल कामोडिटी एक्सचेंज– एनसीडीईएक्स में 2009 में 8,03,842 करोड़ के कुल उत्पादन में से मात्र 0.28 प्रतिशत अर्थात् 2243 करोड़ रूपए की सुपुर्दगी हो पाई।

13. तिकडमबाजी वाली बिक्री। मांग कीमतें बढ़ा रही हैं। आखिर आप इसका लाभ किसे पहुंचाना चाहते हैं?

lVVckth dk\ frdMeckth dk\
cgjk"Vh; dEifu;k dk\
ljdkj d e=h [kk|&dfe;k@de mRiknu d
ckj e [kke[;kyh d c;ku nrs jgrs gA

14. खाद्य उत्पादन की कमियों के बारे में कल्पनात्मक भविष्यवाणियां करके आप किन निहित स्वार्थी लोगों के हित साध रहे हैं?

■

दिल्ली : कैग रिपोर्ट का खुलासा

कांग्रेस सरकार ने बेवजह बढ़ा दिया बसों का किराया

Mh टीसी की बसों में किराए की बढ़ोतरी पर कैग ने आपत्ति जताई है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने उदाहरण देते हुए कहा कि देश के अन्य महानगरों में औसत टिकट दर कम होने के बावजूद स्थानीय परिवहन अगर मुनाफे में है तो फिर डीटीसी घाटे में कैसे है। ज्ञात हो कि निवंबर, 2009 में डीटीसी का न्यूनतम किराया तीन से बढ़ाकर पांच रूपये व अधिकतम 10 से बढ़ाकर 15 रूपये कर दिया गया था।

दिल्ली विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, डीटीसी की औसत टिकट दर प्रति यात्री 55 पैसा प्रति कि. मी. थी, जबकि सीएसटीसी कोलकाता व बीएमटीसी बेंगलुरू की टिकट दर 49 पैसा के बावजूद मुनाफे में हैं। बेंगलुरू राज्य परिवहन निगम इसी टिकट दर में 230 करोड़ रूपये की कमाई कर चुका है। किराए की एक सरकारी समिति ने मई 2007 में हर स्लैब में एक रूपया किराया बढ़ाने की सिफारिश की थी। सरकार ने हांलाकि कम से कम किराए को दो से तीन रूपये बढ़ाने का फैसला लिया, जबकि अन्य किसी तरह के किराए की बढ़ोतरी की मंजूरी नहीं थी। अगर समिति की सिफारिशों को मान लिया गया होता तो निगम 77.08 करोड़ रूपये की कमाई कर सकता था। डीटीसी की आमदनी भी एक चौथाई ही है यानी खर्चा 119. 27 रूपये प्रति किलोमीटर है, जबकि आमदनी केवल 25.90 रूपये प्रति किलोमीटर है।

रिपोर्ट में लो फ्लोर बसों की खरीद के फैसले पर सवालिया निशाने लगाते हुए कहा गया कि इनके खरीदने का फैसला लेते समय घाटा–मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया गया। रिपोर्ट में दिल्ली फायर सर्विस को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा गया है कि महकमे में आधे कर्मचारियों से काम चलाना पड़ रहा है। दिल्ली की 812 ऊंची इमारतों और 846 निजी व सरकारी स्कूलों में भी आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं है। प्रगति मैदान में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए कभी जरूरी एनओसी नहीं ली गई और न ही पालिका बाजार को वर्षों से एनओसी जारी किया गया है।

दक्षिण भारत में भाजपा के बढ़ते कदम

54 वर्ष में बेंगलूर में पहली बार भाजपा का महापौर

बेंगलूर दो साल पहले कर्नाटक की सत्ता हासिल कर दक्षिण में सरकार बनाने का रिकार्ड बनाने वाली भाजपा ने एक बार फिर इतिहास बना दिया। बेंगलूर नगरपालिका के 54 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा का महापौर होगा। 198 सदस्यीय वृहत् बेंगलूर महानगरपालिका के लिए 28 मार्च को हुए चुनाव में भाजपा ने 110 सीटें अपने नाम की हैं। कांग्रेस को 60 और किंगमेकर की भूमिका में आने की उम्मीद पाले बैठे जनता दल–सेक्युलर को महज 14 सीटें मिलीं।

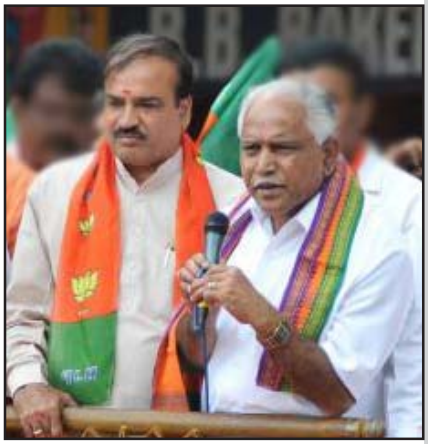

मुख्यमंत्री बी.एस. येद्दयुरप्पा ने इस जीत को राज्य सरकार में जनता के विश्वास का नतीजा करार दिया। अगले महीने सरकार की दूसरी सालगिरह मनाने जा रही भाजपा इस जीत से बेहद उत्साहित है। इसका प्रदर्शन करने के लिए शहर में सैकड़ों भाजपाइयों ने जुलूस निकाला। मई, 2008 में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा था।

अब एक और जीत से उत्साहित येद्दयुरप्पा ने कहा– यह हमारे विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब है। उन्होंने देश के इस हाईटेक शहर में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए तीन साल में 22,500 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान भी किया। विधानसभा चुनाव में बेंगलूर नगरपालिका क्षेत्र की 17 सीटों पर भाजपा जीती थी, जबकि कांग्रेस 10 और जनता दल–सेक्युलर एक सीट पर ही सिमट कर रह गई थी।

लोकसभा चुनाव में बेंगलूर क्षेत्र की सभी तीन सीटें भाजपा के खाते में गई थीं। नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी के लिए निजी झटका है। दोनों जनता दल–सेक्युलर की ओर से जबरदस्त प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर भाजपा को बेंगलूर की सत्ता से बेदखल करने की नीति भी बना रहे थे। ■

कर्नाटक में विकास के नये आयाम

रंग ला रही है मुख्यमंत्री की कवायद

राज्य में निवेश आकर्षित करने की मुख्यमंत्री श्री बीएस येड्डियूरप्पा की कवायद रंग ला रही है। मुंबई में दो दिवसीय रोड शो के बाद मुख्यमंत्री के सामने दिग्गज कंपनियों निवेश की रूचि जाहिर की। शो के आखिरी दिन येड्डियूरप्पा ने कहा कि राज्य में बिजली के भारी संकट को देखते हुए राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को उच्च वरीयता दे रही है। राज्य सरकार ने कम से कम 15 हजार मेगावाट क्षमता की ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा था। इस शो के दौरान एल एंड टी के अलावा राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम (एनटीपीसी) भी राज्य के बीजापुर जिले में 4000 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके अलावा श्री रेणुका इन्फ्रा प्रोजेक्टस ने भी राज्य पे ताप ऊर्जा के क्षेत्र में 5500 करोड़ रूपए का निवेश करने की स्वीकृति प्रदान की है।

भू-अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू

श्री येड्डियूरप्पा ने कहा कि राज्य में उद्योगों की स्थापना के राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 2500 से लेकर 5000 एकड़ तक भूमि अवाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। औद्योगिक निवेश से राज्य के लोगों के लिए रोजगार सृजन तो होगा ही, साथ ही किसानों को बिजली व अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

विदेशों में भी होगा रोड शो

राज्य सरकार ने 3 व 4 जून को राजधानी बेंगलूरू में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया है और मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री निराणी ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, हांगकांग, सिंगापुर सहित विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित करके राज्य में निवेश के अवसरों की जानकारी देने की पहल की है। ■

मनमोहन के शासनकाल में गरीबों की संख्या बढ़ी

विश्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा

मनमोहन सिंह के 6 साल के राज में भारत में अमीरी और गरीबी की खाई और अधिक चौड़ी हुई है। अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब हो गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 17 फीसदी लोग अरबों रूपए और अपार संपत्ति के मालिक बन गए हैं। वे स्वयं को अमरीकी रईसों की बराबरी वाला मानने लगे हैं। जबकि 83 फीसदी जनता गरीबी में जीवन जी रही है। उसे न भर पेट भोजन मिल रहा है न न्यूनतम मजदूरी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार और उड़ीसा की स्थिति घाना से भी खराब है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने वाले पानी के मामले में भारत की हालत भयंकर खराब होती जा रही है। भारत के 110 करोड़ लोगों में से 62 करोड़ लोग अति पिछड़े राज्यों में रहते हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार उड़ीसा और झारखंड में देश की एक तिहाई आबादी रहती है। इन राज्यों में शासन का स्तर भी खराब है लेकिन विकसित राज्य गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाल और किसान मृत्युदर सर्वाधिक पिछड़े घोषित राज्यों (बिहार, उड़ीसा, झारखंड आदि) से भी ज्यादा है।

अब विश्व बैंक भी कहने लगा है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो अमीरी व गरीबी की खाई और भयंकर व चौड़ी होती जाएगी जिसके चलते सामाजिक और राजनीतिक टकराहट आंदोलन विकराल होता जाएगा। यानी नक्सली आंदोलन की तर्ज पर पूरे देश में अमीरों के खिलाफ बगावत हो सकती है। भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ी है। इन दोनों के चलते गरीबी तेजी से बढ़ रही है। राजनीति, शिक्षा, विशेषाधिकार देश की शहरी अमीर आबादी व उद्योगपतियों, नेताओं, नौकरशाहों, व्यापारियों, ठेकेदारों, कार्पोरेट प्रबंधकों के हाथ में सिमटता जा रहा है। काली कमाई और काले धन की एक अलग समानांतर अर्थव्यवस्था सरकार की अघोषित मदद से चल रही है।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 17 फीसदी लोग अरबों रूपए और अपार संपत्ति के मालिक बन गए हैं। वे स्वयं को अमरीकी रईसों की बराबरी वाला मानने लगे हैं। जबकि 83 फीसदी जनता गरीबी में जीवन जी रही है। उसे न भर पेट भोजन मिल रहा है न न्यूनतम मजदूरी।

क्वात्रोच्चि जैसे दलालों को गिरफ्तार करवाने व सजा दिलवाने में देश के प्रधानमंत्री की जगहंसाई का डर लगा रहा है। इसलिए ऐसे दलालों को अघोषित रूप से मनमोहनी सरकार बाइज्जत बरी कराने का उपक्रम कर रही है। देश की जनता को चूस कर काला धन बनाए और विदेशी बैंकों में जमा किए 70 लाख करोड़ रुपए से अधिक काले धन को लाने में मनमोहनी सरकार आनाकानी कर रही है। केवल चिट्ठी–पत्री का हवाला दे रही है कि इस देश को यह लिखा है, उस देश को वह लिखा।

इस तरह सोनिया की मनमोहनी सरकार ने भारत की पूरी आर्थिक नीति ही अमीर तबके को लाभ वाली बनाकर आगे बढ़ा रही है। ऊंची विकास दर इन्हीं अमीरों से जुड़ी है। इसलिए विकास दर बढ़ने के साथ देश में अरबपतियों, खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसी अनुपात में देश में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यानी सस्ते दर पर सर्विस सेक्टर वर्करों के नाम पर गुलामों की फौज एक गहरी अर्थ नीति के तहत तैयार की जा रही है। यह अर्थ नीति अमरीका व यूरोपीय देशों सहित भारत के धनपतियों के उद्योग–धंधों के लिए सस्ते दर पर मजदूर या कर्मचारी मुहैया कराने के लिए है। पांच साल पहले भारत में 8 खरबपति थे, इस समय 57 हो गए हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खरबपतियों का हिस्सा 12 साल पहले मात्र दो फीसदी था, जो अब बढ़कर यह 22 फीसदी हो गया है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में है कि भारत में खेती पर निर्भर 65 फीसदी आबादी का जीडीपी में हिस्सा घटकर 17 फीसदी हो गया है। इससे धनी औश्र गरीब, कृषि एवं उद्योग के बीच के अंतर और गांवों व शहरों के बीच की खाई चौड़ी हुई है। सरकार जो भी गरीबों की मदद के नाम पर योजनाएं चला रही है वे सब की सब विश्व बैंक और अमीर देशों के ऋण से चल रही हैं। ब्याज सहित उसकी भरपाई भारत की जनता को करनी पड़ेगी।

अमरीका व यूरोप में रिसेशन व मंदी के चलते उन देशों की पूंजी किसी भी रूप में भारत जैसे भारी जनसंख्या वाले देश में लगे और उस पर कमाई हो यह उन देशों की योजना है जो विदेशी कर्ज से तमाम योजनाएं गरीबों के नाम पर चल रही हैं, उनमें से 80 प्रतिशत तक रकम नेताओं, नौकरशाहों, ठेकेदारों आदि की जेब में जा रहा है।■

बहुत हो चुका, अब सख्त कार्रवाई का वक्त

एक तरफ दिल्ली में 7 फरवरी, 2010 को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कहते हैं, 'नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है।' वहीं दूसरी ओर, 4 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद प्रभावित इलाकों–लालगढ़ और मिदनापुर के दौरे पर गए हमारे गृहमंत्री पी. चिदंबरम माओवाद विरोधी अभियान में सेना को शामिल किए जाने की मांग ठुकराते हुए कहते हैं, 'हमने माओवादियों के सामने वार्ता का ताजा प्रस्ताव रखा है।' और इस दौरे के महज दो दिन बाद 06 अप्रैल, 2010 को नक्सली छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बर्बर हमले कर सीआरपीएफ के 76 जवानों को घेर कर मार डालते हैं। वास्तव में नक्सलियों ने लोकतांत्रिक भारत के अस्तित्व को चुनौती दी है।

नक्सलियों को नेस्तनाबूत करने का साहस गृहमंत्री को दिखाना चाहिए तो वो अच्छी अंग्रेजी में पिलपिला बयान देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? कब तक गरीब, आदिवासियों, किसानों की लाशें ढेर होती रहेंगी? कब तक हमारे जवान नालायक नेताओं की वजह से नक्सली–आतंक के शिकार होते रहेंगे? कब जागेगी हमारी सरकार और कब जागेंगे हम? आख़िर कब?

पिछले चार दशकों से हमारा देश नक्सली आतंकवाद का दंश झेल रहा है। नक्सली आतंक से उपजे हालात ने आज देशवासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। नक्सलियों के साथ समझौता करनेवाली कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार के शासन में उनके हौसले बुलंद हैं। वे सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों के खून से न जाने कौन सी क्रांति की इबारत लिख रहे हैं? स्कूल भवनों, रेल पटरियों, सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य केन्द्रों को बमों से उड़ाकर न जाने किस तरह के विकास का वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं?

सामाजिक परिवर्तन से नक्सलवाद का कोई लेना–देना नहीं है, वस्तुतः यह एक विशुद्ध आतंकवाद है, जिसका लक्ष्य येन–केन–प्रकारेण सत्ता कब्जाना है। नक्सलवाद मानवता का दुश्मन है। यह भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा है। यह सिरफिरे लोगों का गिरोह है जो जनता व जवान के खून से भारत की धरती को बस लाल करना जानते हैं। सच में ये रक्तपिपासु हैं। ये राष्ट्रद्रोही हैं।

सामाजिक परिवर्तन से नक्सलवाद का कोई लेना–देना नहीं है, वस्तुतः यह एक विशुद्ध आतंकवाद है, जिसका लक्ष्य येन–केन–प्रकारेण सत्ता कब्जाना है। नक्सलवाद मानवता का दुश्मन है। यह भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा है। यह सिरफिरे लोगों का गिरोह है जो जनता व जवान के खून से भारत की धरती को बस लाल करना जानते हैं। सच में ये रक्तपिपासु हैं। ये राष्ट्रद्रोही हैं।

25 मई, 1967 को पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हुए भूमि विवाद में जमींदार और किसानों के बीच संघर्ष हुआ। बंगाल पुलिस ने 11 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। यहीं से नक्सलवाद की चिंगारी भड़की। माकपा से अलग हुए चारू मजूमदार व कानू सान्याल ने इस असंतोष का नेतृत्व किया।

नक्सलवाद का सिद्धान्त है 'सत्ता बंदूक की नली से निकलती है।' नक्सलवादी 'वर्ग शत्रुओं' का कत्लेआम कर क्रांति लाना चाहते हैं। उनका भारतीय लोकतंत्र मे विश्वास नहीं है। वे चुनावों का बहिष्कार करते हैं। वे हिंसा के माध्यम से सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि 21 सितंबर 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन हुआ। माओवादियों का सैनिक संगठन 'पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) है।'

माओवादियों से प्रभावित क्षेत्र को 'रेड कॉरिडोर' के नाम से जाना जाता है। यह 'रेड कॉरिडोर' आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार से होते हुए नेपाल के माओवादी ठिकानों को जोड़ता है। नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आदिवासी बाहुल्य है। ये ऐसे जंगलवासी हैं जो सदियों से शोषण का शिकार हैं।

नक्सली समस्या भारतीय शासन व्यवस्था की विफलता की निशानी है। आज भी आजादी के 62 साल बाद बहुसंख्यक आबादी को पीने का साफ पानी नसीब नहीं है। बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अशिक्षा के चलते लोगों का जीवन अंधकारमय है। भूख व कुपोषण से मौतें हो रही है। जानलेवा कर्ज है। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं।

नक्सली आतंकवाद की भयानक तस्वीर:

- 2009 के आंकड़ों के अनुसार नक्सलवाद देश के 20 राज्यों की 220 जिलों में फैल चुका हैं।
- पिछले तीन साल (2007–08 तथा 2009) में देश में नक्सली हिंसा के कारण 1405 लोग मारे गए जबकि 754 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए।
- भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुताबिक देश में 20,000 नक्सली काम कर रहे हैं।
- लगभग 10,000 सशस्त्र नक्सली कैडर बुरी तरह प्रेरित और प्रशिक्षित हैं।
- आज देश में 56 नक्सल गुट मौजूद हैं।
- करीब 40 हजार वर्ग किलोमीटर इलाका नक्सलियों के कब्जे में हैं।
- नक्सली करीब 1400 करोड़ रुपए हर साल रंगदारी के जरिए वसूलते हैं।
- नक्सली भारतीय राज्य को सशस्त्र विद्रोह के जरिए वर्ष 2050 तक उखाड़ फेंकना चाहते हैं।

नक्सलवादी इसी स्थिति का लाभ उठाकर अपना संकीर्ण स्वार्थ साधते हैं। वे लोगों को जनता के राज का सपना दिखाकर उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं।

अब युवा माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर क्रांतिकारी नहीं बनते। माओवादियों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बेरोजगार युवाओं को गुमराह करना शुरू कर दिया है। माओवादियों ने उनसे जुड़ने वाले हर युवा को 3 हजार रूपए प्रतिमाह तनख्वाह तथा रंगदारी से उगाही गई रकम में से भी कमीशन देने की बात कही है। इस लालच में फंस कर माओवादियों से जुड़ रहे युवाओं को लेकर गृहमंत्रालय ने चिंता जताई है।

दूसरी ओर, सर्वहारा के शासन का सपना देखनेवाले नक्सलियों के शिविर में अब क्रांतिकारी साहित्य बरामद नहीं होते। हाल ही में एक नक्सली Bangetudi शिविर में छापे के दौरान पुलिस ने ब्लू फिल्म की सीडी, प्रयुक्त और अप्रयुक्त कंडोम, माला डी की गोलियां और शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक दवाएं जब्त कीं। इसके साथ ही यह रहस्योद्घाटन हुआ है कि बड़ी तेजी से नक्सली एचआईवी/एड्स से पीड़ित हो रहे हैं और इसके चलते कई नक्सलियों की मौतें भी हुई हैं। एड्स समेत तमाम यौन जनित रोगों के शिकार हो रहे हैं। नक्सलियों पर यौन शोषण का इतना भूत सवार हो रहा है कि वे नाबालिगों को भी नहीं बख्श रहे है। संगठन में शामिल युवती चाहकर भी इसके खिलाफ न आवाज उठा पा रही है और न ही अपने घर वापस लौट पा रही हैं। समूचे रेड कॉरिडोर में अनपढ़ आदिवासी महिलाओं को बिन ब्याही मां बनाया जा रहा है। वास्तव में महिलाओं का यौन शोषण और निर्दोष लोगों की हत्या ही तो नक्सली क्रांति का असली रूप है। ➡

पूरी तरह केंद्र सरकार की विफलता है नक्सली हमला

vftr Mkoky] iol fun'kd vkbich

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला पूरी तरह केंद्र सरकार की विफलता है। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में यह सरकार की राजनीतिक विफलता होने के साथ–साथ नक्सलवाद के मुकाबले के लिए बना, गए सरकार के तंत्र की भी विफलता है। इसमें खुफिया तंत्र, सुरक्षा बलों की तैनाती और रणनीति सभी की विफलता शामिल है।

पिछले छह साल से भारत सरकार नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रही है। सरकार कई बार इसका ऐलान कर चुकी है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए, उसकी हकीकत ऐसे हमलों से सामने आ रही है। नक्सली हमले बढ़ते जा रहे हैं। उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। सरकार सिर्फ दावे और घोषणाएं कर रही है। उसमें उनसे निपटने की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। केंद्र सरकार इसे राज्य सरकार के सिर पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, क्योंकि जो जवान मारे गए हैं वे केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के थे। केंद्रीय गृह मंत्री दो तीन साल में नक्सलवाद के खात्मे की बात कहते हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों के उनके दौरे के फौरन बाद दंतेवाड़ा में नक्सली हमला होता है। आखिर खुफिया तंत्र यह पता क्यों नहीं लगा पा रहा है कि नक्सलियों को हथियार कहां से मिल रहे हैं? उनके मददगार कौन हैं? उन्हें पैसा कहां से मिल रहा है? उनके पूरे तंत्र को हम क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? आतंकवाद के मसले पर तो सरकार पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन नक्सली शिविर तो देश के भीतर ही हैं। उन्हें नष्ट करने में क्या अड़चन है। सेना के प्रयोग से भी कोई फायदा होता नजर नहीं आता है, क्योंकि असली प्रश्न सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। ■

पिछले दिनों केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने मानवाधिकार विभाग के सम्मेलन में भरोसा दिलाया कि देश के माओवाद प्रभावित इलाकों को अगले तीन साल में नक्सलियों के चंगुल से मुक्त करा लिया जाएगा।

गृह सचिव जी. के. पिल्लई ने रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) में एक जनसमूह को संबोधित करते हुए 06 मार्च 2010 को कहा कि वर्ष 2050 तक नक्सली भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पिल्लई ने स्वीकार किया कि नक्सलवाद प्रभावित राज्यों को नक्सलियों को कुचलने की स्थिति में आने में अभी सात से 10 वर्ष लगेंगे। नक्सली हिंसा को रोकने के लिए सरकार कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है। इसी के चलते नक्सली हिंसा में लगातार इजाफा होता जा रहा है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत हैं, जिसका संप्रग सरकार में अभाव दिखता है। कभी सरकार नक्सलवाद को आतंकवाद की श्रेणी में रखती है तो कभी बातचीत के लिए टेबल पर बुलाती हैं। सरकार का यह ढुलमुल रवैया बेहद चिंताजनक हैं। आज जिस तरीके से देशभर में नक्सली हमले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए केन्द्र और राज्य में समन्वय हो। पुलिस संख्या बल में इजाफा हो। सुरक्षा बलों को बेहतर प्रशिक्षण मिले। अत्याधुनिक हथियार मिले। वास्तव में अब सख्त कार्रवाई का वक्त आ गया है। इसके साथ ही आम जनता को भी स्यापा छोड़कर नक्सली आतंकवाद के खात्मे के लिए जन–अभियान चलाना चाहिए। ■

डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान संगोष्ठी

हम अपनी सेना को कहीं भी रखने के लिए हैं स्वतंत्र

हम अपनी सेना को चाहे जम्मू–कश्मीर में रखें या केरल में, इस मामले में न तो किसी अन्य देश को ऐतराज होना चाहिए और न ही हमारी सेनाओं को हटाने के लिए दबाव डालना चाहिए। यह विचार इंटेलीजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री अजीत डोवल ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान द्वारा आयोजित संगोष्ठी के दौरान व्यक्त किया। श्री अजित डोवल ने कहा कि बार–बार विदेशी शक्तियां जम्मू–कश्मीर से सेना हटाने के लिए दबाव डालती हैं। सरकार ने पिछले कुछ महीनों के दौरान बड़ी संख्या में सेना को घाटी से अन्यत्र स्थानांतरित किया है, जो बड़े खेद की बात है। यह हमारा अंदरूनी मामला है और इसे मामले में हमें किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। संगोष्ठी में मौजूद पूर्व उच्चायुक्त श्री जी. पार्थसारथी ने कहा कि आज भी पाकिस्तान की विदेश नीति और शासन पाकिस्तानी सेना के चुगंल में है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेशी मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान दौरे के दौरान वहां के मंत्रियों से तो संक्षिप्त मुलाकात की, लेकिन पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कियानी से काफी देर तक मुलाकात की और रात का भोजन भी किया। इससे स्पष्ट होता है कि पाक शासन में वहां की सेना की बड़ी भूमिका है। उन्होंने बताया कि जम्मू–कश्मीर में तो बड़े पैमाने पर स्वायत्तता दी गई है, लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अभी तक कोई स्वायत्तता नहीं दी गई है और इस मामले में कोई विदेशी शक्ति आवाज नहीं उठाती है। ज्ञात हो कि जम्मू–कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर आयोजित इस संगोष्ठी में उपस्थित लोगों ने बड़े पैमाने पर जम्मू–कश्मीर और वहां की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की।

> ***सरकार ने पिछले कुछ महीनों के दौरान बड़ी संख्या में सेना को घाटी से अन्यत्र स्थानांतरित किया है, जो बड़े खेद की बात है। यह हमारा अंदरूनी मामला है और इसे मामले में हमें किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है।***

लद्दाख यूटी मोर्चा के संरक्षक श्री थुतान छेवांग ने डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी के कथन का हवाला देते हुए कहा कि एक ही देश में दो विधान, एक ही देश में दो प्रधान और एक ही देश में दो निशान की नीति को हमें त्यागनी होगी अन्यथा हम देश में एकता और अखंडता नहीं ला सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख श्री मदन दास देवी ने कहा कि आज भी हम अपनी सेनाओं को पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू–कश्मीर मामले पर हमें आपसी द्वेष को भूलकर एकजुट होने की जरूरत है। इस संगोष्ठी में भाजपा के वरिष्ठ नेता, श्री बाळ आपटे, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन, शोध अधिष्ठान के निदेशक श्री तरूण विजय व अन्य अनेक नेतागण उपस्थित थे। ■

भाजपा ने हैदराबाद दंगों की न्यायिक जांच की मांग की

Hkkरतीय जनता पार्टी हैदराबाद में मंदिरों, हिन्दुओं और गायों पर हुए अकारण हमलों की घटनाओं की न्यायिक जांच किए जाने की मांग करती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कांग्रेसी सांसद श्री मधु यास्की के इस बयान की पृष्ठभूमि में कि ये आक्रमण वर्तमान मुख्यमंत्री के. रोसैय्या को अस्थिर करने के षड्यंत्र का हिस्सा हैं और नगर पुलिस आयुक्त की इस स्वीकृति के बाद कि ये आक्रमण पूर्व–नियोजित हैं, यह जांच और अधिक लाज़मी हो जाती है। पूर्वोक्त दोनों बयान न्यायिक जांच को जरूरी ठहराने के लिए पर्याप्त गंभीर है क्योंकि उनसे सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के षड्यंत्र के बड़े इरादे का संकेत मिलता है। कांग्रेसी नेताओं के स्वयं के बीच राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने हेतु ऐसे पूर्व–नियोजित सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का आंध्र प्रदेश का एक इतिहास रहा है, जैसाकि 1990 में एम. चेन्ना रेड्डी के शासनकाल के दौरान देखा गया था। पुलिस आयुक्त के बयान के मजमून से भी इसका इसी तरह का खुलासा होता है। जब इन पूर्व–नियोजित हमलों की पुलिस आयुक्त को जानकारी थी, तब उन्होंने सबसे पहले इन घृणित हमलों को रोकने की योजना पर अमल क्यों नहीं किया ? इस घटना को इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस और एम.आई.एम. (Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) गठबंधन ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन में सत्तारूढ़ है।

श्री जावडेकर ने कहा कि एम.आई.एम. जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों तथा कुछ अन्य लोगों ने श्रीराम के होर्डिंग लगाने और हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर झंडे टांगे जाने पर आपत्ति की थी और मंदिरों, दुकानों, घरों पर हमले करने शुरू कर दिए थे – यहां तक कि उन्होंने गौशाला को भी अपना निशाना बनाया था। कार्रवाई करने के लिए शिकायतों और अपीलों के बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ए.टी.एम. से बाहर आ रहे मिस्टर सत्यनारायण को पुलिस की मौजूदगी में छुरा घोंपकर मौत की नींद सुला दिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस के इस निकम्मेपन का पूरा फायदा उठाया और शमशेरजंग में प्रसिद्ध जैन गौशाला पर धावा बोल दिया। उपद्रवियों ने घास और पैट्रोल डालकर वहां तीन गायों को ज़िन्दा जला दिया। उन्होंने वहां खड़ी कारों को आग लगा दी और पुराने शहर के पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने लोगों की पिटाई की। पुलिस ने गाय जलाने और छुरा घोंपने के घृणित कार्यों में लिप्त उपद्रवियों को इस समय तक गिरफ्तार नहीं किया है। यह आन्ध्र प्रदेश की सरकार और पुलिस की घोर तथा व्यापक विफलता है।

श्री जावडेकर ने मंदिरों, दुकानों, घरों पर किए गए हमलों और छुरेबाजी की घटनाओं के अतिरिक्त गाय जलाने के कायरतापूर्ण कृत्य, जो उपद्रवियों की निकृष्ट क्रूरता दर्शाता है, की घोर भर्त्सना करते हुए कहा कि भाजपा उपद्रवियों और उसके पीछे शरारती दिमाग रखने वाले लोंगों को गिरतार किए जाने की भी मांग करती है। भाजपा गलती करने वाले पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने की भी मांग करती है। ■

जांच समिति का गठन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन गडकरी ने हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद, श्री प्रकाश जावडेकर के नेतृत्व में एक पांच सदस्य समिति का गठन किया है, जो वहाँ जाकर स्थिति का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी।

समिति के अन्य सदस्य निम्न प्रकार है :

1. श्री प्रहलाद जोशी (सांसद, लोकसभा)
2. श्रीमती निर्मला सीतारमण (राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा)
3. डॉ० लक्ष्मण (राष्ट्रीय सचिव, भाजपा)
4. श्री के. बी. शानप्पा (सांसद, राज्यसभा)

तालिबान के साथ बातचीत के खिलाफ भाजपा की चेतावनी

संवाददाता द्वारा

अधिकारिक स्रोतों को उद्धृत करते हुए समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत सरकार अपनी अफगान नीति में परिवर्तन कर रही है और उसने तालिबान तथा गुलबुद्दीन हिकमतयार की अध्यक्षता वाले हिज़्ब–ए–इस्लामी ग्रुप के साथ बातचीत करने की इच्छा दर्शायी है। उक्त विचार गत 29 मार्च 2010 को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री तरुण विजय ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जैसा कि रिपोर्टों ने दर्शाया है, यदि यह सही है तो भारत की अफगान नीति में हुए इस बदलाव का खुलासा लोगों के सामने किया जाना चाहिए और विदेश मंत्री को उन प्रतिगामी तत्वों से बातचीत के प्रति इच्छा दर्शाने के raison d'être` का उत्तर देना चाहिए, जो आई.एस.आई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जिनके भारत विरोधी कार्यों ने पिछले दो दशकों से हमें लहु–लुहान कर रखा है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ वार्ता किए जाने से वह सब उलट गया है, जिस पर भारत अब तक डटा हुआ था। वे ओसामा के आदमी हैं, वे अपनी औरतों को पर्दे के पीछे धकेलते हैं, उन्हें स्कूल जाने से रोकते हैं, उनकी दुनिया एक अंधेरे की दुनिया है, जो समाज को मध्य युग में पहुंचाती है और जो लोकतंत्र तथा बहुलवाद से बहुत दूर है। वे नशीली दवाओं के बदले प्राप्त धन पर जीवित रहते हैं और उनकी सहायता के प्रमुख स्रोत में पाकिस्तान की आई.एस.आई. मुख्य रूप से शामिल है। भारत के प्रति उनका जिहाद जग–जाहिर है।

यह विश्वास करते हुए कि अमेरिका अफगानिस्तान को बहुत जल्द छोड़ सकता है, Post-US Strategy की योजना बनाना नौसिखियापन है। भारत अब तक अफगानिस्तान में 1.2 बिलियन डॉलर से भी अधिक का निवेश कर चुका है। यह तर्कसंगत है कि हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वहां भारत क्या प्राप्त करना चाहता है जहां पर भारत की भूमिका को अत्यधिक प्रभाव वाली अमेरिकन उपस्थिति और अमेरिकन कार्यों ने हाशिए पर लाकर छोड़ दिया है।

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त, गुलबुद्दीन हिकमतयार का ग्रुप हिज़्ब–ए–इस्लामी बहुत थोड़े प्रभावहीन लोगों के निरर्थक गुट के रूप में सिमटकर रह गया है। यह उल्लेखनीय है कि गुलबुद्दीन हिकमतयार ने 1975 में पाकिस्तान में आई.एस.आई. और सी.आई.ए. के साथ मिलकर अफगान में रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए हिज़्ब–ए–इस्लामी की स्थापना की थी। रिपोर्टों के अनुसार 11 सितंबर, 2001 की घटनाओं के फलस्वरूप पश्तून नस्ल के हिकमतयार ने तालिबान नेता मौहम्मद उमर और देश में कायदा ग्रुप के शेष बचे लोगों के साथ कोइलेशन विरोधी गठबंधन बनाया था। अमेरिका ने उसको अलकायदा को उसके पिछले समर्थन के कारण फरवरी 2003 में आतंकवादी घोषित किया था। 19 फरवरी, 2003 को यह घोषणा की गई थी कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसा संकेत देने वाली सूचना है कि गुलबुद्दीन हिकमतयार ने अलकायदा और तालिबान द्वारा किए गए आतंकवादी कृत्यों में भाग लिया था और उनका समर्थन किया था। उसके आतंकवादी कार्यकलापों के कारण अमेरिका ने हिकमतयार को Specially Designated Global Terrorist के रूप में पदनामित कर दिया था। भारत के Intelligence intercepts से भी खुलासा हुआ था कि आई.एस.आई. कर्मचारी भारत के विरुद्ध और अफगान स्थित भारतीय प्रतिष्ठानों के विरूद्ध हमला करने के लिए न केवल लश्करे–तैय्यबा के साथ बल्कि अफगानिस्तान के अन्य ग्रुपों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं। इनमें से सबसे पहला गत वर्ष सितंबर में कुनार में हुआ था, जिसमें आई.एस.आई., तालिबान नेताओं और हिज़्ब–ए–इस्लाम गुलबुद्दीन जैसे तत्वों की आवभगत लश्करे तैय्यबा ने की थी, जिसका अध्यक्ष आई.एस.आई. लैकी और रैबिड इंडिया–बेटर गुलबुद्दीन हिकमतयार है।

उन्होंने यह भी कहा कि ये वे ही लोग हैं, जो पत्थर मारकर, लैम्प पोस्ट से लटकाकर मृत्यु देने जैसे समरी पनिशमेंट देते है तथा बामियान को ध्वस्त करते हैं। ये लोग काबुल में भारतीयों को मारने के भी जिम्मेवार थे। क्या भारत सरकार को उनके साथ वार्ता शुरू करनी चाहिए ?

यदि भारत के पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में कोई रणनीति है तो वह प्रमुखतया भारतीय हितों को सुरक्षित रखने और भारत विरोधी आतंकवादी ग्रुपों का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए। खून के प्यासे तत्वों के साथ कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। हेडली मुद्दे की विफलता और अमेरिकी दबाव के तहत पाकिस्तान के साथ निरर्थक वार्ता के पश्चात् संप्रग की भारत विरोधी तत्वों के साथ कभी खत्म न होने वाले समझौतावादी रवैयों की यह एक अन्य स्तब्धकारी घटना है।■

हिन्दू-इज्म और महाकुम्भ का इन्साइक्लोपीडिया

गत सप्ताह इण्डिया हेरिटेज फाउण्डेशन के सहयोग से रूपा एंड कं. द्वारा ग्यारह खण्डों में प्रकाशित ''इन्साइक्लोपीडिया आफ हिन्दू–इज्म'' के एक विशेष पूर्व–प्रस्तुति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके तीन खण्डों को विवेकानन्द फाउण्डेशन सभागार, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में प्रदर्शन के लिए रखा गया। इस कार्यक्रम में ''हिन्दू–इज्म इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड'' अर्थात् ''समसामयिक विश्व में हिन्दू धर्म'' पर एक पैनल चर्चा हुई।

मैं भी उन 400 श्रोताओं में शामिल था जिन्होंने इस ज्ञानवर्धन और आनन्ददायक चर्चा को बड़े ध्यान से सुना, जो दो घण्टे तक चलती रही। प्रतिष्ठित विद्वानों में स्वामी आत्मा प्रियनंदा, वाइस–चांसलर, श्री रामकृष्ण विवेकानंद विश्वविद्यालय, डॉ. कपिल कपूर, प्रधान सम्पादक, इन्साइक्लोपीडिया आफ हिन्द–इज्म, डॉ. कविता शर्मा, डायरेक्टर, इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर, डॉ. लोकेश चन्द्र, प्रख्यात विद्वान एवं लेखक तथा साध्वी भगवती, सेक्रेटरी, इण्डिया हेरिटेज रिसर्च फाउण्डेशन शामिल थे।

सांध्यकाल में हुई इस चर्चा का जो विषय और प्रयोजन रहा, उसने मुझे ऐसी बहुत सी चर्चाओं का स्मरण करा दिया जिन्हें मैंने कभी कराची में विद्यार्थी रहते हुए अपनी किशोरावस्था में सुना था।

मेरा जन्म 1927 में हुआ और मैंने अपने जीवन के प्रथम बीस वर्ष ब्रिटिश शासन में गुजारे थे। जब मैं स्कूल का विद्यार्थी ही था, तभी से मुझे पुस्तकें पढ़ने का बड़ा चाव था। उन दिनों एक पुस्तक पढ़ी जो केथरीन मायो द्वारा लिखित 'मदर इण्डिया' थी। यदि कोई भारतीय इस पुस्तक को पढ़ता तो या तो उसे अपने देश, संस्कृति और धर्म पर शर्म महसूस होने लगती या फिर वह उन ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से नफरत करने लगता जिन्होंने देश में इस प्रकार का वातावरण बनाया, जो इस प्रकार की कुख्यात पुस्तकों में लिखा गया था। गांधी जी ने इस पुस्तक को 'ड्रेन इंस्पेक्टर रिपोर्ट' की संज्ञा दी थी। मेयो की पुस्तक के प्रत्युत्तर में अनेक पुस्तकें लिखी गईं थीं। उनमें से एक पुस्तक लाला लाजपतराय की ''अनहैप्पी इण्डिया'' थी।

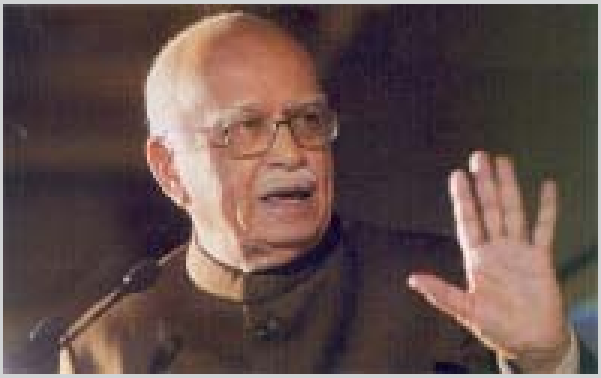

कुम्भ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह है परन्तु कोई ठीक से बता नहीं पाएगा कि यह कितना बड़ा मेला है। शायद ईश्वर ही श्रद्धालुओं का रिकार्ड रखता होगा जो ऐसे समारोह में इलाहाबाद से गंगा और यमुना नदियों मे अपने पाप धोने के लिए आते हैं।

विवेकानन्द फाउण्डेशन के इस आयोजन में इन्साइक्लोपीडिया के प्रधान सम्पादक डॉ. कपूर ने बड़े जोरदार ढंग से कहा कि हमारे देश के अभिजात्य वर्ग के लोगों ने पश्चिमी संस्कृति को प्रवेश करने दिया जिसका कारण यह रहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान हम पश्चिमी संस्कृति वाले देशों ने अपनी शिक्षा प्रणाली हम पर लाद दी। जिसे सुनकर मुझे अत्यंत शर्म महसूस हुई और अपनी परम्परा, समारोहों और रीति–रिवाजों तथा विशेष रूप से अपनी भाषा–विशेष रूप से संस्कृत– के बारे में खेद हुआ।

मुझे थामस मैकाले के जीवन का दृष्टांत स्मरण हो आया जब मैकाले ने 1836 में अपने पिता को बड़े गर्व से लिखा था– ''हिन्दुओं पर इस (इंगलिश) शिक्षा का असर विलक्षण होगा। जिस हिन्दू को भी यह शिक्षा मिलेगी वह कभी भी अपने धर्म के साथ ईमानदारी से जुड़ा नहीं रह पाएगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना को अपनाया जाएगा तो आज से तीस वर्ष बाद बंगाल में कोई भी सम्मानीय वर्ग का व्यक्ति बुतपरस्त नहीं रह पाएगा।''

राजधानी में इसी प्रकार के एक समारोह का आयोजन कुम्भ समारोह के चलते अप्रैल के आरम्भ में ऋषिकेश में हुआ। पूजनीय स्वामी चिदानंदजी, प्रधान, इण्डिया हेरीटेज रिसर्च फाउण्डेशन ने, जिन्होंने दो दशक पूर्व इन्साइक्लोपीडिया आफ हिन्दू–इज्म की कल्पना की थी, इस समारोह में श्रद्धेय दलाई लामा को आमंत्रित किया।

◆◆◆

हरिद्वार महाकुम्भ 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से चल रहा है। यह अप्रैल के मध्य तक बैसाखी पर्व तक चलता रहेगा।

मार्क टुली 25 वर्षों से साउथ एशिया के बीबीसी संवाददाता और न्यूजमैन रहे हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने निष्कासित कर दिया था, तब वे दिल्ली में बीबीसी ब्यूरो के प्रमुख थे। उन्होंने 1999 में ''नो फुल स्टाप इन इण्डिया'' नाम की पुस्तक लिखी थी। श्री टुली ने कुम्भ समारोह की भारी प्रशंसा करते हुए लिखा :–

''कुम्भ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह है परन्तु कोई ठीक से बता नहीं पाएगा कि यह कितना बड़ा मेला है। शायद ईश्वर ही श्रद्धालुओं का रिकार्ड रखता होगा जो ऐसे समारोह में इलाहाबाद से गंगा और यमुना नदियों मे अपने पाप धोने के लिए आते हैं। जहां तक हम लोगों का सम्बंध है, आज सेटेलाइट फोटोग्राफ, कम्प्यूटर और आधुनिक टेक्नालाजी की अनेक प्रणालिया हैं, जिनसे काफी कुछ सही अनुमान लगाया जा सकता है, परन्तु जिनका उपयोग इस प्रयोजन के लिए हो नहीं पाया है। अतः इतना ही कहा जा सकता है कि सरकारी अनुमान है कि 1977 के कुम्भ मेला के अत्यधिक पावन अवसर पर 10 मिलियन लोगों के स्नान किया।''

''विश्व का कोई भी भी अन्य देश कुम्भ मेला जैसा नजारा पेश नहीं कर सकता है। वैसे तो भारतीय प्रशासक बहुत बदनाम है फिर भी यह उनकी विजय है, परन्तु उनसे भी ज्यादा भारत के लोगों की है। और उधर देखिए कि अंग्रेजी भाषी प्रेस की प्रतिक्रिया इस विजय पर क्या है? निश्चित ही, द्वेषपूर्ण। देश के सर्वाधिक प्रभावशाली समाचार पत्र टाइम्स आफ इण्डिया ने एक लम्बा लेख प्रकाशित किया जिसमें ऐसे बहुत से शब्दों की भरमार थी– 'कुम्भ में रूढ़िवाद छाया रहा', 'कुम्भ में धार्मिक हथधर्मिता विवेक पर हावी रही', और ''आखिर कुम्भ बस हंगामा बन कर रह गया, परन्तु सार के नाम पर कुछ नहीं रहा'' टाइम्स आफ इण्डिया ने हिन्दू विश्व परिषद की राजनीति की आलोचना की परन्तु विश्लेषण करने का जरा प्रयास नहीं किया और न ही उन लाखों लोगों की धर्मपरायणता का उल्लेख किया जिन्होंने संगम में स्नान किया।''

मार्क टुली का जन्म कोलकाता में हुआ। परन्तु वह बीबीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी नई दिल्ली में रहे और उन्होंने भारत को ही अपना स्वदेश माना। टुली उन बुद्धिजीवियों में सर्वोच्च स्थान रखते है जिन्होंने बहुत सही ढंग से सेक्युलरिज्म की भारतीय अवधारणा को समझा है। उन्होंने बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि 'सेक्युलर स्टेट' का मतलब 'अधार्मिक राज्य' से नहीं है। वह मानते हैं कि भारत में सेक्युलरिज्म का मूल आधार ही हिन्दू सहिष्णुता है।

◆◆◆

मार्क टुली का जन्म कोलकाता में हुआ। परन्तु वह बीबीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी नई दिल्ली में रहे और उन्होंने भारत को ही अपना स्वदेश माना। टुली उन बुद्धिजीवियों में सर्वोच्च स्थान रखते है जिन्होंने बहुत सही ढंग से सेक्युलरिज्म की भारतीय अवधारणा को समझा है। उन्होंने बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि 'सेक्युलर स्टेट' का मतलब 'अधार्मिक राज्य' से नहीं है। वह मानते हैं कि भारत में सेक्युलरिज्म का मूल आधार ही हिन्दू सहिष्णुता है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है:

''प्रातःकाल दिल्ली में जब मैं उठा तो मुझे बीबीसी वर्ल्ड रेडियो सर्विस पर एक बहस सुनने को मिली जिसमें कहा गया था कि कोई भी क्रिस्मस कार्ड न भेजे क्योंकि वे लोग सेक्युलर नहीं है। सेक्युलरिस्ट सभी ब्रिटेनवासियों का मजा खराब करना चाहते है, वे क्रिस्मस वे सभी रंगों, लंदन आक्सफोर्ड स्ट्रीट की लाइटों, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लगे क्रिस्मस वृक्षों, घर–घर में गुंजते केरोल गायकों के गीत बिगाडना चाहते हैं क्योंकि ये सभी ईसाइयत का प्रदर्शन हैं। प्रस्ताव था कि फूहड किस्म के प्रेरणाविहीन संदेश हो– ''हैप्पी मिड–विंटर फैस्टीवल।''

इन विचारों को सुनने के बाद मुझे एक राष्ट्रीय दैनिक 'हिन्दू' की कापी देखने को मिली, जिसके मुख पृष्ठ पर एक चित्र छपा था जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कोलकाता में अपने घर के बगीचे में बच्चों के लिए क्रिस्मस पार्टी कर रहे थे। यह राज्यपाल गोपाल गांधी थे और वह अपने दादा के नक्शे कदमों पर चल रहे थे जिन्होंने एक बार कहा थाः ''मेरा हिन्दू धर्म मुझे हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है।'' लालकृष्ण आडवाणी नई दिल्ली 28 मार्च 2010। ■

इससे भारतीय समाज में अलगाव पैदा होगा : रामनाथ कोविन्द

Hkkरत सरकार ने 29 अक्टूबर, 2004 को राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट 18 दिसम्बर, 2009 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्र इस आयोग के सभापति थे। इसीलिए इस आयोग को उन्हीं के नाम पर "रंगनाथ मिश्र आयोग" के रूप में जाना जाता है।

इस आयोग की उक्त रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी। आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षा, सरकारी रोजगार और सामाजिक कल्याण स्कीमों में पिछड़ा वर्ग कोटा के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस 15 प्रतिशत आरक्षण में से 10 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देने की और शेष बचे 5 प्रतिशत आरक्षण को अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को देने की सिफारिश की गई है। आयोग ने आगे यह भी सिफारिश की है कि धर्मांतरित दलित ईसाइयों और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया जाए।

वर्तमान में धर्मांतरित मुस्लिमों और ईसाइयों को पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अर्न्तगत सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। प्रश्न यह उठता है कि जब उन्हें पिछड़ा वर्ग श्रेणी में पहले से ही आरक्षण प्राप्त हो रहा है, तब वे अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण क्यों चाहते है ? इसका उत्तर स्पष्ट है। उनकी विशेष रूचि सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि वे ग्राम पंचायतों से लेकर लोकसभा तक के चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति की श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि वे पिछड़ा वर्ग आरक्षण के तहत आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं बन सकते हैं। यदि सरकार रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है, तो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के पात्र बन जाएंगे। इस प्रकार, अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों और राजनीतिक क्षेत्रों में अपने शेयर को धर्मांतरित ईसाइयों और मुस्लिमों के साथ बांटना पड़ेगा।

धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की मांग सबसे पहले पूना पैक्ट के बाद 1936 में उठाई गई थी, जब ब्रिटिश शासन के दौरान अनुसूचित जातियों की पहली सूची प्रकाशित की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने यह कहते हुए, इस मांग को खारिज कर दिया था कि "कोई भी भारतीय ईसाई अनुसूचित जाति की श्रेणी की मांग करने का हक़दार नहीं है।" अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को अंतिम रूप से अस्वीकृत कर दिया गया था।

संविधान सभा में चर्चा के दौरान धर्मांतरितों को आरक्षण प्रदान करने की मांग भी उठाई गई थी। किंतु, डॉ० अम्बेडकर, श्री जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस मांग को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया था कि हिन्दुओं को छोड़कर किसी अन्य धर्म के अनुयायी को कोई आरक्षण मंजूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि तथाकथित अनुसूचित जातियां शताब्दियों से अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव की यंत्रणा झेल रही हैं।

इसके अतिरिक्त, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून, 1961 को सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित अपने पत्र में धर्म–आधारित आरक्षण को स्पष्ट रूप से नामंजूर कर दिया था।

वर्ष 1996 में तत्कालीन नरसिम्हाराव सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक अध्यादेश के माध्यम से धर्मांतरित ईसाइयों तथा मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना चाहा था किंतु, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने उक्त अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इसी प्रकार 1997 में, देवगौड़ा सरकार धर्मांतरितों को अनुसूचित जातियों में शामिल किए जाने के बारे में संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहती थी। किंतु, इस विधेयक को प्रतिपक्षी दलों द्वारा कड़े विरोध के कारण लाया नहीं जा सका था। बाद में राज्य सरकारों से इस विधेयक पर अपनी राय देने के लिए कहा गया था और राज्य सरकारों ने भी इसका विरोध किया था।

कर्नाटक के कांग्रेसी नेता श्री हनुमन्थप्पा के सभापतित्व के अर्न्तगत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने भी धर्मांतरित ईसाइयों तथा मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों

की सूची में शामिल किए जाने की मांग को अस्वीकृत कर दिया था। बाद में उक्त आयोग के सभी परवर्ती सभापतियों अर्थात् डॉ. सूरजभान, श्री विजय सोनकर शास्त्री तथा वर्तमान सभापति श्री बूटा सिंह ने भी इसी के अनुरूप निर्णय किया।

उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों के जरिए स्पष्ट राय व्यक्त की है कि धर्मांतरित दलित ईसाइयों तथा मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों के समान नहीं माना जा सकता है।

निष्कर्ष यह है कि ब्रिटिश सरकार, संविधान सभा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग तथा उच्चतम न्यायालय – सभी ने एक स्वर से राय व्यक्त की है कि धर्मांतरितों को अनुसूचित जाति का दर्जा मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। आप जानते ही हैं कि अनुसूचित जातियों के बच्चों का शैक्षिक स्तर धर्मांतरित ईसाइयों तथा मुस्लिमों के बच्चों के शैक्षिक स्तर से कहीं अधिक निम्न रहता है। अतः धर्मांतरितों के बच्चे सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बड़े भाग को हड़प कर जाएंगे। धर्मांतरित दलित ईसाई तथा मुस्लिम अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के पात्र हो जाएंगे। अतः, अनुसूचित जातियों को सभी क्षेत्रों में सभी कोणों से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इससे धर्मांतरण को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा भारतीय समाज का ताना–बाना पूरी तरह छिन्न–भिन्न हो जाएगा।

26 जनवरी, 2010 को भारतीय संविधान ने अपने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं किंतु, इतनी लंबी अवधि के बावजूद अनुसूचित जातियों का आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास तथा सशक्तिकरण इस कारण से सुस्त रहा है कि सरकार की स्कीमों का कार्यान्वयन उचित रूप में नहीं किया जा सका। आज भी समाज के इस वर्ग को सरकारी स्कीमों का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अब अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों के आरक्षण अनुपात को बढ़ाने के बजाय धर्मांतरित दलित ईसाइयों तथा मुस्लिमों को उनके 15 प्रतिशत आरक्षण में से आरक्षण का शेयर देने के बारे में सोच रही है। इसके कारण अनुसूचित जाति के लोगों के हितों को भारी क्षति होगी। ■

अनुसूचित जातियों के बच्चों का शैक्षिक स्तर धर्मांतरित ईसाइयों तथा मुस्लिमों के बच्चों के शैक्षिक स्तर से कहीं अधिक निम्न रहता है। अतः धर्मांतरितों के बच्चे सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बड़े भाग को हड़प कर जाएंगे। धर्मांतरित दलित ईसाई तथा मुस्लिम अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के पात्र हो जाएंगे। अतः, अनुसूचित जातियों को सभी क्षेत्रों में सभी कोणों से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, इससे धर्मांतरण को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा भारतीय समाज का ताना–बाना पूरी तरह छिन्न–भिन्न हो जाएगा।

सोलापुर (महाराष्ट्र)

अमिताभ मसले पर चव्हाण पर चौतरफा हमला

पुणे में हुए अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ मंच पर उपस्थित रहने से मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के कन्नी काटे जाने पर भाजपा और शिवसेना ने उन पर चौतरफे हमले का सिलसिला जारी रखा है। सोलापुर में जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने चव्हाण पर हमला बोला, वहीं मुंबई में वरिष्ठ भाजपा नेता श्री गोपीनाथ मुंडे और शिवसेना प्रवक्ता निलम गोर्हे ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाला। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने सोलापुर में कहा कि मुख्यमंत्री चव्हाण ने मराठी साहित्य सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित रहने का वादा पूरा न कर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी साहित्यकारों और कलाकारों का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। इसी तरह का बयान मुंबई में श्री गोपीनाथ मुंडे ने दिया।

विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चव्हाण को गांधी परिवार के डर से मराठी साहित्य सम्मेलन में जाने के अपने कार्यक्रम में तब्दीली करनी पड़ी। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने अमिताभ के संदर्भ में उल्लेख करते हुए कहा कि बांद्रा–वरली सी लिंक के चार नये लेन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रण मिलने पर जाकर बिग बी ने कोई गलती नहीं की। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को इतने बड़े कलाकार के साथ भेदभाव करना शोभा नहीं देता है। उसे मराठी साहित्य सम्मेलन में अमिताभ के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उपस्थित न रहने का फरमान सुनाने के लिए माफी मांगना चाहिए। ■

खाद्य सुरक्षा से पहले वितरण सुधारिए

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए बिना योजना कामयाब नहीं होगी

'kkrk dsekj

देश के 53 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के कानूनी मसौदे को मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने मंजूरी दे दी है। लगभग एक वर्ष तक विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और देश के प्रत्येक गरीब को 25 किलो अनाज तीन रुपये प्रति किलो की दर से प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। विधेयक के मसौदे में यह भी प्रावधान है कि यदि इन गरीबों को अनाज नहीं मिला, तो खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। देश की आधी से अधिक जनसंख्या को इस कानून के माध्यम से सस्ता अनाज मिलेगा। सरकार की इस कवायद से भुखमरी समाप्त होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के इस मसौदे में गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को अनाज के मामले में कोई राहत प्रदान नहीं की गई है।

बीपीएल परिवार प्रत्येक राज्य में वही होंगे, जिन्हें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है। यानी राज्यों के बीपीएल परिवारों या योजना आयोग के बीपीएल परिवारों के आंकड़ों में अगर कोई अंतर होगा, तो अतिरिक्त परिवारों के लिए दिए जाने वाले बीपीएल अनाज का व्यय संबंधित राज्य सरकार ही उठाएगी। इस कानून के बाद बीपीएल परिवारों को हर महीने 35 किलो की जगह अब सिर्फ 25 किलो अनाज मिलेगा। खाद्य सुरक्षा की इस मुहिम को खासकर ऐसे देश में शंका की दृष्टि से देखा जाना स्वाभाविक है, जिसे वैश्विक भूख सूचकांक की 88 देशों की सूची में 68वां आंका गया है

देश के कुछ राज्य तो ऐसे हैं, जहां भूख से होने वाली मौतों की संख्या सालोंसाल बढ़ती जा रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां अकाल पड़ा रहता है, तो कुछ राज्यों में अनाज इतना अधिक होता है कि संग्रहण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वह खुले आकाश के नीचे सड़ता–गलता रहता है! हाल ही में पंजाब के कुछ जिलों से लाखों टन गेहूं सड़ने की खबर आई थी। गेहूं की खरीद का काम भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें संग्रहण की व्यवस्था न होने का दोष केंद्र सरकार पर मढ़ती हैं, जबकि केंद्र राज्यों को दोषी बताकर पल्ला झाड़ लेता है।

भारत जैसे देश में गरीबों को अनाज पहुंचाने का काम आसान नहीं है, क्योंकि यहां की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। जिस प्रक्रिया से यह राशन गरीबों तक पहुंचता है, वह प्रक्रिया केवल त्रुटिपूर्ण ही नहीं, भारतीय संदर्भ में विफल भी रही है। वर्ष 1997 के बाद सरकार द्वारा लक्षित वितरण प्रणाली के अंतर्गत गांवों में स्थापित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न, मिट्टी तेल आदि वितरित किया जाता है। इन दुकानों से वितरित अनाज कई वजहों से गरीबों तक नहीं पहुंचता। इसका सबसे बड़ा कारण है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार। वर्ष 2008 में जारी योजना आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रणाली के तहत 42 प्रतिशत सब्सिडीकृत अनाज ही लक्षित वर्ग तक पहुंचता है। दूसरे शब्दों में 58 फीसदी अनाज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। हमारे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है, जहां 5,03,070 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा गांव–गांव तक सब्सिडीकृत अनाज गांव–गांव तक पहुंचाया जाता है। राज्यों में उचित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था न होने के कारण

वर्तमान प्रणाली गरीबों तक सस्ता राशन नहीं पहुंचा रही। इसके लिए कई बार गरीबों को कैश कूपन देने का सुझाव आया। ब्राजील में यह प्रयोग सफल रहा है। लिहाजा अपने यहां भी इसे आजमाया जा सकता है। जाहिर है, गरीबों को कूपन मिलेंगे, तो वे किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री खरीद लेंगे। इससे जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है, वहीं वितरण व्यवस्था भी सुधर सकती है।

वितरण व्यवस्था का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता। उचित मूल्य की इन दुकानों पर अनाज समय पर न पहुंचने की शिकायतें भी अक्सर सुनने को मिलती हैं।

अनाज न पहुंचने का एक बड़ा कारण है राज्यों द्वारा आबंटित राशन का समय पर वितरण न किया जाना। इस व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के लिए गरीबों को अनाज के कूपन वितरित किए जाने चाहिए, ताकि वे किराने की किसी भी दुकान से सुविधापूर्वक सामान खरीद सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भयंकर भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार अब कैंसर का रूप ले चुका है। केंद्र सरकार गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए 28,000 करोड़ रुपये देती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक पूरा अनाज नहीं पहुंचता। अंत्योदय परिवार सबसे गरीब परिवार है। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। अंत्योदय परिवारों को भी 35 किलो अनाज दिया जाता था। लेकिन अब जहां इसकी मात्रा घटाकर 25 किलो कर दी गई है, वहां अनाज की दर भी दो रुपये की जगह तीन रुपये कर दी गई है। यह तो खाद्य सुरक्षा में पीछे हटने की बात है। दस साल पहले वाजपेयी सरकार ने सबसे गरीब व्यक्ति के लिए जो सहूलियतें दी थीं, उन्हें कम नहीं करना चाहिए। दोषमुक्त वितरण प्रणाली में गरीबों की वास्तविक संख्या के बारे में खाद्यान्न अधिकार मामले पर अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीपी बधवा ने कहा है कि जिन लोगों की दैनिक आय 100 रुपये है, उन्हें खाद्य सब्सिडी दी जाए और उन्हें गरीब समझा जाए। इस आधार पर देश के पचास करोड़ लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आ जाएंगे। न्यायपालिका की इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए 82,100 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट यह रिपोर्ट स्वीकार कर लेती है, तो सरकार को हर हाल में इसे मानना पड़ेगा।

न्यायपालिका के इस निर्णय से अथवा सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम से गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा मिल पाएगी, इस पर विभिन्न कृषि अर्थशास्त्रियों द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। गरीबों की संख्या के बारे में भिन्न–भिन्न मत इस संदर्भ में और कठिनाई पैदा करते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनाज न मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का भी प्रावधान है, लेकिन उस भत्ते का क्या लाभ, अगर अनाज तक गरीब की पहुंच ही न हो? बीपीएल परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना बनाकर प्रत्येक वर्ष गरीब परिवारों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए अन्य लक्षित कार्यक्रम भी बनाए जा सकते हैं।

वर्तमान प्रणाली गरीबों तक सस्ता राशन नहीं पहुंचा रही। इसके लिए कई बार गरीबों को कैश कूपन देने का सुझाव आया। ब्राजील में यह प्रयोग सफल रहा है। लिहाजा अपने यहां भी इसे आजमाया जा सकता है। जाहिर है, गरीबों को कूपन मिलेंगे, तो वे किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री खरीद लेंगे। इससे जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है, वहीं वितरण व्यवस्था भी सुधर सकती है। ■

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

खाद्य पदार्थों में तेजी बदस्तूर जारी

महंगाई रोकने की सरकार की तमाम कोशिश नाकाम साबित हो रही है। खुदरा बाजार में दालों की कीमत फिर चढ़ना शुरू हो गई हैं। जबकि खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकारी आंकड़ें बताते हैं कि 20 मार्च को समाप्त सप्ताह में खाद्य उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर 16.35 फीसदी हो गई है। इससे पहले सप्ताह में महंगाई दर 16.22 फीसदी थी। बाजार में अब खाद्य उत्पादों से इतर महंगाई की आंच ईंधन उत्पादों पर भी दिखने लगी है। यही वजह है कि समीक्षाधीन सप्ताह में पेट्रोल का दाम एक वर्ष पूर्व की तुलना में 16.82 फीसदी हाई स्पीड डीजल 14.99 फीसदी महंगा हुआ है। वहीं दालों, दूध, मसालों के दाम फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। साल दर साल की बात करे तो दालें 31.55 फीसदी, फल 10.06 फीसदी, दूध 18.74 फीसदी और अनाज 10. 04 फीसदी महंगा हुआ है। थोक मूल्यों पर आधारित खाद्य पदार्थों का साप्ताहिक सूचकांक 0.6 फीसदी बढ़ गया है।

इस दौरान जौ और दूध में तीन–तीन फीसदी, मूंग व मसालों में दो–दो फीसदी और अरहर के दाम में एक फीसदी की तेजी आई है। जबकि चाय, मछली और गेहूं की कीमतों में कमी आई है। इसके अलावा मूंगफली और खोपरा के दाम घटने से गैर खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हुई हैं। इन पदार्थों के इंडेक्स में 0. 1 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। सरकार उम्मीद कर रही है कि नई फसल आने के बाद खाद्य उत्पादों में महंगाई का असर कम होगा। मगर महंगाई का असर अब सभी क्षेत्रों पर दिखने लगा है। मासिक आधार पर फरवरी में महंगाई दर 9.89 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। इससे पहले जनवरी में यह 8.56 प्रतिशत थी। कयास लगाए जा रहे कि महंगाई रोकने के लिए आरबीआई अप्रैल में घोषित होने वाली मौद्रिक समीक्षा के दौरान रेपो, रिवर्स रेपो और सीआरआर की दरों में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकता है। हालांकि पिछले महीने ही आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो दरों में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की थी। ■

महंगाई के विरोध में दिल्ली भाजपा का उग्र प्रदर्शन

अनेकों नेता और कार्यकर्ता घायल

महंगाई के विरोध में दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में दिल्ली भाजपा के नगर निगम पार्षदों ने दिल्ली विधानसभा पर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व नगर निगम में दल के नेता सुभाष आर्य ने किया। स्थायी समिति के अध्यक्ष रामकिशन सिंघल, उपाध्यक्ष रजनी अब्बी उप महापौर आजाद सिंह, पूर्व महापौर आरती मेहरा और स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता समेत नगर निगम के सभी क्षेत्रों के अध्यक्षों और पार्षदों ने प्रदर्शन में भाग लिया।

प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल ने भी प्रदर्शन में भाग लिया और प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया।

प्रदेश भाजपा के पार्षद और प्रमुख नेता बैलगाड़ी में सवार होकर प्रदर्शनकारियों की भीड़ के साथ विधानसभा की ओर बढ़े। पुलिस ने अवरोध लगाकर उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और उन्हें तितर–बितर करने के लिए पानी की तेज बौछार की। पानी की तेज बौछार से कई कार्यकर्ता घायल हुए और उन्हें चोंट आई। स्थायी समिति के अध्यच रामकिशन सिंघल के कंधे और बांह में फ्रैक्चर हुआ है और उन्हें बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरतार कर तिमारपुर थाने ले गई जहां बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि महंगाई सिर्फ तभी बढ़ती है, जब कांग्रेस सत्ता में आती है। उन्होंने प्रश्न किया कि देश की जनता निरंकुश महंगाई से त्राहि–त्राहि कर रही है और उधर ऐसा लगता है कि मानो महंगाई पर नियंत्रण पाना कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताओं में ही नहीं है। सरकार की न कृषि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के बारे में और न कृषि की उत्पादन लागत कम करने के बारे में कोई नीति है। यह कैसी सरकार है तो एक वस्तु को सस्ते में निर्यात करती है और फिर उसी वस्तु को महंगे में आयात करती है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में जो बजट पेश किया है, वह बेरहमी भरा बजट है। रसोई गैस, प्रेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी करने के अलावा आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर वैट दो से ढाई गुना कर दिया है। शीला दीक्षित की असंवेदनशील सरकार ने लालटेन और किरोसिन स्टोव जैसी गरीबों के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं पर वैट में भारी वृद्धि की है।

भाजपा नेता, पार्षदों व कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल

दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने महंगाई के मुद्दे पर जनता के उबलते हुए रोष को अभिव्यक्त करने के लिए अपने पार्षद दल को बधाई दी। प्रो. कोहली ने कहा कि केन्द्र और दिल्ली की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनरोष का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और 21 अप्रैल को लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग संसद पर एकत्र होकर प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति को महंगाई के विरोध में करोड़ों हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन भी दिया जाएगा। ■

तुष्टिकरण की नीति से देश को खतरा

Hkkजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति की आलोचना करते हुए 6 अप्रैल 2010 को कहा कि यह देश की एकता के समक्ष खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने एक जन सभा में कहा कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति ने देश के ढांचेए इसकी एकता और अखंडता के टूटने का खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा, 'अल्पसंख्यक समुदाय को तुष्ट करने और तथाकथित बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच एक विभाजन पैदा करने की क्या जरूरत है।' उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि वह आतंकवादियों की तुष्टिकरण की एक अन्य नीति भी अपना रही है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका में 9/11 हमले के बाद एक भी हमला नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में यह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रोजमर्रा की बात हो गई हैए सत्तारूढ़ पार्टी की नीति का शुक्रिया।' उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों को आश्रय देने को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की। दुनिया का कोई भी देश घुसपैठियों को बसने की इजाजत नहीं देता है। यह सिर्फ हमारे देश में दिखाई देता है, जहां हजारों बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। कांग्रेस यह काम अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए कर रही है। असम में घुसपैठियों की समस्याओं ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। कांग्रेस और संप्रग की गलत आर्थिक नीतियों तथा कुशासन ने महंगाई बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई की दर सबसे अधिक 11 फीसद है। उन्होंने राजग और संप्रग सरकारों के शासन काल के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का तुलनात्मक आंकड़ा भी दिया। ■

मूल्य वृद्धि पर श्वेत पत्र की मांग

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने देश में मूल्य स्थिति के बारे में श्वेत–पत्र जारी किए जाने को 5 अप्रैल, 2010 को गुवाहटी में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में मांग की। वे पूर्वोत्तर राज्यों में अपने दौरे के दूसरे दिन गुवाहाटी में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कांग्रेस सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान क्यों छू रहे हैं जब :

- देश में भरपूर फसल हुई है और यथेष्ट बफर स्टॉक मौजूद है।
- सरकारी गौदाम क्षमता से अधिक भरे पड़े हैं।
- लाखों टन खाद्यान्न सड़ रहा है।
- विश्व बाजार में खाद्य पदार्थों का मूल्य आधा है।

fQj D;k

- मूल्य वृद्धि कम नहीं हुई है।
- मुद्रास्फीति एक बार फिर दो अंकों में पहुंच गई है।
- भारत में मुद्रास्फीति 11 प्रतिशत है जबकि अमेरिका, चीन, यूरोप, मलेशिया में मुद्रास्फीति 1 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक है।
- खाद्य पदार्थों के मूल्य में 20 प्रतिशत के आसपास वृद्धि हुई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवीनतम अनुमान चालू वर्ष में गेंहू के रिकार्ड उत्पादन अर्थात् 82 मिलियन टन का संकेत करते हैं जोकि 2006/07 में 75 मिलियन टन था। सरकार द्वारा चीनी का उत्पादन 141 लाख टन बताया गया था, जो अब 178 लाख टन के करीब पहुंच गया है। श्री गडकरी ने कहा कि दो दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी से 14 प्रश्न पूछे थे, जिनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यह डॉ. मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की घोर विफलता है। ■

प्रांतीय परिषद का अधिवेशन सम्पन्न

अतीत से सबक लेकर संवारें भविष्य

Hkkजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा के प्रांतीय परिषद के अधिवेशन में कार्यकर्ताओं से भविष्य के प्रति उम्मीद बनाए रखने को कहा। श्री लालकृष्ण आडवाणी ने केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार को देश को विखंडन के कगार पर पहुंचाने के लिए दोषी बताया। उन्होंने कहा कि देश में दो विधान व दो प्रधान की नीति चल रही है। आजादी के पचास वर्षों बाद ऐसा होना देश के लिए खतरनाक है। इस दौरान उन्होंने कभी लाहौर को याद किया तो कभी गुलामी की वेदना का जिक्र किया। कश्मीर के लिए परमिट व्यवस्था खत्म करने तथा राष्ट्रध्वज को फहराने के लिए दी कुर्बानी को भी बताया। जनसंघ के दौर में क्या हुआ और आपातकाल में किस तरह लोगों को जेलों में ठूंसा गया, इस पर भी कार्यकर्ताओं को वस्तुस्थिति से अवगत कराया। भाजपा में पद और कद के बीच क्या भेद है, यह भी समझाने का प्रयास रहा। नसीहत दी गई कि पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उद्देश्य हासिल करने पर जो कद बनता है, वह अधिक अहम है। बैठक में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि भाजपा मात्र विधायक या सांसद बनने के लिए ही चुनाव नहीं लड़ती वरन देश का एजेंडा तैयार करने में उसका चुनाव अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने देश के भाजपा शासित राज्यों की विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए सराहना की।

उन्होंने कहा कि विकास के ऊंचे पायदान हासिल करने वाले तीन राज्यों में भाजपा शासित राज्यों का होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है। भाजपा प्रदेशों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का माध्यम बताते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि 20वीं सदी भले पश्चिमी देशों की रही लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी और भाजपा इसकी नींव तैयार करके रहेगी।

देश की मौजूदा हालात पर भी श्री आडवाणी ने कहा कि अंग्रेजों ने जो धारणा बनाई, उस पर चलकर हिंदुस्तान का एक–एक व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो रहा है। ऐसे में अतीत के गौरवबोध होने पर सभी में दायित्वबोध की भावना प्रबल हो जाएगी।

भाजपानीत उत्तराखण्ड की सरकार को विकासोन्मुख बताते हुए उन्होंने निशंक सरकार की पीठ थपथपाने में भी कंजूसी नहीं बरती। उनका कहना था कि महाकुम्भ का जैसा आयोजन इस बार हुआ वह अनुकरणीय है आज तक के इतिहास में ऐसा महाकुम्भ कहीं नहीं हुआ।

कार्यपरिषद की बैठक में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री बच्ची सिंह रावत एवं नए अध्यक्ष श्री विशन सिंह चुफाल भी उपस्थित थे।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे पार्टी के लिए प्रश्न नहीं, बल्कि उत्तर बनकर खड़े हों। उन्होंने नारा दिया कि जहां पार्टी की पहुंच कम है, वहां हम अवश्य पहुंचे। परिषद् ने दो प्रस्ताव भी पारित किए गए। कार्यपरिषद के समापन संबोधन में श्री रामलाल ने राज्य में सरकार होने के कारण कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को भी वाजिब बताया तो साथ में नसीहत देते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपेक्षा कर सकते हैं पर पूरी न होने पर वजह जाने बिना कोई ऐसा कदम न उठाएं जो पार्टी के हित में न हो। कार्यपरिषद में सर्व सम्मति से पारित राजनीतिक प्रस्ताव में सूबे की सरकार के कामों पर मुहर लगाई गई तो राज्य की उपेक्षा करने पर केंद्र सरकार की तीखी भर्त्सना करते हुए इन मुद्दों को आम जनता के बीच रखने की बात की गई है। जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्षा बीना आर्य की ओर से रखे गए एक प्रस्ताव में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया गया और 21 अप्रैल को दिल्ली में प्रस्तावित भाजपा के विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। ■

प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पूर्णकालिकों की संयुक्त बैठक संपन्न

Hkkरतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि देश की जनता महंगाई का दंश भुगत रही है। इससे जहां आम आदमी की थाली खाली हो गयी है, वहीं आम आदमी के मुंह से निवाला भी छिन गया है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पीड़ा को संसद के अधिवेशन में आक्रामक ढंग से मुखरित कर चुकी है। 21 अप्रैल को अभूतपूर्व विशाल राष्ट्रीय प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और संसद का घेराव कर जनता की पीड़ा को जबान दी जाएगी। श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि महंगाई के विरोध में हमारा आंदोलन संसद से सड़क तक जारी रहेगा। 21 अप्रैल का आंदोलन अब तक का सर्वाधिक और बड़ा जन भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

सुषमा स्वराज 26 मार्च 2010 को भोपाल प्रदेश कार्यालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला चुनाव अधिकारियों और पूर्णकालिकों की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने की। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव थावर चंद गेहलोत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, माया सिंह सहित पार्टी के अन्य प्रदेश पदाधिकारी, सांसद और विधायक भी उपस्थित थे। नरेन्द्र सिंह तोमर ने सुषमा स्वराज का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। जिलाध्यक्ष आलोक संजर सहित प्रदेश के 55 जिलों से आए जिलाध्यक्षों ने भी सुषमा स्वराज का स्वागत किया और उन्हें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए उनके यशस्वी दीर्घ जीवन की कामना की। पूर्व में नरेन्द्र सिंह तोमर ने डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्जवलित किया। प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, प्रदेश सह संगठन महामंत्री भगवतशरण माथुर, अरविन्द मेनन, प्रदेश उपाध्यक्ष विजेन्द्रसिंह सिसोदिया, अनिलमाधव दवे, चंद्रमणि त्रिपाठी, विनोद गोटिया, सुधा जैन, प्रदेश महामंत्री नंदकुमार सिंह चौहान, फग्गनसिंह कुलस्ते, रामोराम गुप्ता, प्रदेश मंत्री अरविन्द भदोरिया, रामेश्वर शर्मा, बाबू सिंह रघुवंशी, सरिता देशपांडे, चेतन कश्यप, निर्मला भूरिया, चन्द्रप्रकाश मिश्रा, गोविन्द मालू सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

हर मतदान केन्द्र से कार्यकर्ता दिल्ली जायेंगे - नरेन्द्रसिंह तोमर

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व म.प्र. भाजपा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रदेश में संगठन चुनाव 5 अप्रैल तक पूर्ण कर लिये जाने, पार्टी की परंपराओं के अनुसार चुनाव में सहमति और सौहार्द्र बनाए रखने के साथ 21 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित महंगाई विरोधी आंदोलन में प्रदेश की जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित की। प्रदेश के सभी 7 संभागों के 55 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों से अपने–अपने क्षेत्र में संगठन चुनाव की प्रगति और 21 अप्रैल के महंगाई विरोधी आंदोलन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और आग्रह किया कि इस आंदोलन में प्रत्येक मतदान केन्द्र से कार्यकर्ताओं और जनता की उपस्थिति भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

जनोन्मुखी नीतियों की सफलता का श्रेय संगठन को - शिवराजसिंह चौहान

प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, जिला चुनाव अधिकारियों और पूर्णकालिकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश का संगठन देश में अनुकरणीय है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ज्योति से देश आलोकित होता है। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है। पार्टी की जनोन्मुखी नीतियों पर जनता ने मोहर

'सखी मंच' का स्नेह-मिलन कार्यक्रम संपन्न

गत 11 मार्च, 2010 को नई दिल्ली में 'सखी मंच' द्वारा भाजपा सांसदों की पत्नियों का स्नेह–मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे कल्पना यह थी कि पार्टी भी एक परिवार जैसा है। उसमें परस्पर संवाद, परस्पर विश्वास और प्रेम बढ़े और पारिवारिक भावना कायम हो। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी महिलाओं का परिचय हुआ। इन महिलाओं में बहुत सी शिक्षा, आरोग्य, उद्योग, सामाजिक तथा अन्य प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली थी। इस कार्यक्रम में भाजपा महिला सांसदों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही।

इस तरह का सम्मेलन उनकी व्यक्तिगत पहचान भी बढ़ायेगा और पारिवारिक स्नेह को भी बढ़ावा मिल जायेगा, इस पर सहमति हुई तथा यह सखी मंच नियमित रूप से मिले, इस पर भी सहमति तय हुई। अपने–अपने क्षेत्रों में यह सखियां स्वयं सहायता समूह, ग्रंथालय, शिक्षा, आरोग्य आदि विषयों में समान प्रकल्प चला सकती हैं। इस दिशा में विचार हुआ, तथापि इसका अंतिम निर्णय बाद में होगा।

कार्यक्रम का महत्व देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री आडवाणी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनन्त कुमार भी उपस्थित रहे और उन्होंने मार्गदर्शन किया। जनसंघ के दिनों से ऐसे पारिवारिक सम्मेलन पार्टी की विशेषता रही है। इसका स्मरण दिलाते हुए आदरणीय श्री आडवाणी जी ने कहा, ''यह मंच नियमित रूप से मिलता रहे, इस काम को संस्थागत रूप देना चाहिये। स्नेह– भाव बढ़ाना ही पार्टी के लिए विशेष योगदान है।''पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी ने कहा, ''कोई भी संगठन अच्छे मानवीय संबंधों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। पक्ष का सहयोग इस प्रकल्प में जरूर रहेगा।'' श्रीमती सुषमा जी ने इसको एक अनुठा सम्मेलन माना। सभी बहनों को अपना परिवार संभालने की बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ''हमारा सक्रिय सहयोग ही कार्यकर्ता की ताकत है। लोक सभा, राज्य सभा और पार्टी की पठन सामग्री घर में आती रहती है, उसे रिसार्स बैंक के रूप में देखो और आगे बढ़ो।'' संगठन मंत्री श्री रामलाल जी ने कहा, ''यह संघ परिवार में होता है, आज यह भाजपा में हो रहा है। यह पक्ष के कार्य को गति देगा।''

श्रीमती प्राची जावडेकर के अनुसार, सखी मंच का मिलन संसद के सत्र में संपन्न होगा। हर एक सांसद पत्नियों द्वारा बारी–बारी से इस स्नेह मिलन का आयोजन किया जायेगा। आने वाली 5 मई को श्रीमती तेजस्वनी अनन्त कुमार के घर मिलने का कार्यक्रम तय हुआ।■

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

➔

लगाकर अभी तक के मिथक को तोड़ा है। इसका श्रेय पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं, प्रदेश पदाधिकारियों और जनता को है। आपने प्रदेश में संगठन के चुनाव में लगातार सहमति से निर्णय होने को एक लोकतांत्रिक उत्कृष्ट परंपरा बताया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आपने कहा कि पिछले तीन वर्षों में संगठन के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उर्जित किया और विकास योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाया, उसका श्रेय स्वाभाविक रूप से उन्हीं को समर्पित है। आपने निवृत्त हो रहे जिला पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके यशस्वी भविष्य की कामना की। ■
~~~~~~~~~~